News सिटी चीफ

# सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-194
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

इंदौर, शनिवार 19 अक्टूबर 2024

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

**आज का विचार**

इतना हौसला रखो कि किस्मत को उसके सामने झुकना पड़ेगा

## इंडिया केम 2024: मप्र सरकार बना रहा आकर्षक फार्मा पॉलिसी, मुंबई में मोहन यादव ने बताई खासियत

मप्र सरकार की मोहन यादव सरकार आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। एमपी में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। रायसेन के तामोट, ग्वालियर के बिलोवा में प्लास्टिक पार्क तथा रतलाम में वृहद फार्मा बायोटेक केमिकल जोन विकासित किया जा रहा है। यह बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में आयोजित इंडिया केम 2024 के 13वीं द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में कही। सीएम ने बताया कि 2023-24 में मध्य प्रदेश ने 11 हजार 889 करोड़ के फार्मा प्रोड्क्ट एक्सपोर्ट किए हैं। झाबुआ में मेघनगर में केमिकल उद्योग के लिए आधुनिक अधोसंरचना, धार के बदनावर में पीएम मित्रा पार्क और भोपाल-ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित की गई हैं।सीएम ने बीना स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रो केमिकल परियोजना और गेल इंडिया की परियोजना सहित अन्य अधोसंरचना से अवगत कराया। कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी भी उपस्थित रहेसीएम मोहन यादव ने कहा, मप्र में केमिकल, फार्मा, पेट्रो-केमिकल और प्लास्टिक जैसे उद्योगों के लिए बेहतरीन ईको-सिस्टम विद्यमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में भारत पेट्रोलियम की 50 हजार करोड़ से अधिक की पेट्रो-केमिकल परियोजना का भूमि-पूजन किया। प्रदेश में 35 हजार करोड़ की गेल इंडिया की वृहद पेट्रो-केमिकल परियोजना का काम तेजी से जारी है। इससे 25 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

**रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योग समूहों ने निवेश के लिए की पहल** मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में औद्योगिकीकरण तथा निवेश के क्षेत्र में केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आरंभ किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी हैं। अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शीघ्र ही रीवा में होगी।

## बेनामी संपत्ति लेनदेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया अपना फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 2022 के उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले कानून के दो प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये प्रावधान ऐसे सौदों और संपत्तियों को अधिकारियों की तरफ से कुर्क किए जाने पर रोक लगाते हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 अगस्त, 2022 के फैसले पर केंद्र की समीक्षा याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ की तरफ से दिए गए फैसले को वापस ले लिया। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2022 के अपने फैसले में तब माना था कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धाराएं 3(2) और पांच 'स्पष्ट रूप से मनमानी' होने के कारण असंवैधानिक थीं। अधिनियम की धारा-तीन बेनामी (किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखी गई संपत्ति) लेन-देन पर रोक से संबंधित है, जबकि धारा-पांच कुर्क करने योग्य बेनामी संपत्ति से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों से सहमति जताई कि इन दोनों प्रावधानों की वैधता को तत्कालीन पीठ के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। पीठ ने कहा कि इस मामले को देखते हुए, समीक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक सामान्य कानून है कि किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर पक्षों के बीच जीवंत सुनवाई और विवाद की अनुपस्थिति में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

## सोना 80 हजार रुपए के करीब पहुंचा, चांदी 94,500 रुपए प्रति किलो

नई दिल्ली। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, त्योहारी सीजन की मजबूत मांग के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 550 रुपए की तेजी के साथ 79,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली यह बहुमूल्य धातु 79,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 550 रुपये उछलकर 79,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 78,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस बीच, चांदी 1,000 रुपए उछलकर 94,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। गुरुवार को चांदी 93,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही थी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन में ग्राहकों की खरीदारी बढ़ने से घरेलू बाजार में कीमती धातुओं की मांग मजबूत होकर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मध्य पूर्व में जारी तनाव और आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कारण अनिश्चितता के बीच निवेशक पीली धातु को सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे हैं।

## वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच के रूप में लांच होगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी

उज्जैन। उज्जैन में लगी देश की पहली वैदिक घड़ी की तर्ज पर अब इसे कलाई घड़ी और दीवार घड़ी के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। जल्द ही इस घड़ी का उपयोग मोबाइल एप के जरिये लोग अपने फोन में भी कर सकते हैं। यह जानकारी वैदिक घड़ी के प्रणेता लखनऊ निवासी आरोह श्रीवास्तव ने दी। उज्जैन में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस घड़ी में ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। हर घंटे में अलग-अलग तस्वीरें इस घड़ी में दिखाई देगी। साथ ही देश और दुनियाभर में सूर्यास्त और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी इसमें दर्ज किया जाएगा। इस घड़ी का उपयोग मोबाइल एप के जरिए लोग अपने फोन में भी कर सकते हैं। साथ ही अगर घड़ी में किसी तरह का बदलाव होता है तो वो आपके मोबाइल एप पर भी देखने को मिलेगा। वैदिक घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच 30 घंटे का समय दिखाएगी। साथ ही इसमें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर 60 मिनट नहीं बल्कि 48 मिनट का एक घंटा तय किया गया है। साथ ही वैदिक समय के आधार पर ही यह घड़ी अलग-अलग मुहूर्त भी दिखाएगी। यह घड़ी पुराने समय में जैसे काल और समय की गणना होती थी

## मप्र में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ 12 नवंबर से मिलेंगे ज्वॉइनिंग लेटर

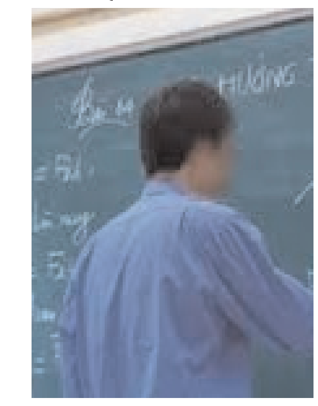

भोपाल। मध्यप्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही नई नियुक्तियां करने जा रहा है। 4 हजार युवाओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति मिल सकती है। यह भर्ती उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) 2023 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए होगी। सरकार अब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ईडब्ल्यूएस के पात्र अभ्यर्थियों की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय दिया है। इसके कारण अब विभाग 12 नवंबर से नियुक्ति पत्र जारी करना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 की भर्ती प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग कर रहे हैं। फिलहाल यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। राज्य में आठ हजार 720 पदों पर भर्ती होनी है। वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराई थी। 29 सितंबर 2022 को नियुक्ति प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई थी। इस कारण 848 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। इस भर्ती को भी वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही किया गया था। तब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी। इस कारण नई भर्ती पर रोक लगा दी गई। अब उच्च न्यायालय ने 848 अभ्यर्थियों को 45 दिन में नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

## '2028' की तैयारी हो गई शुरू सीएम मोहन यादव बोले-

# ऐसी योजना बनाएं कि क्षिप्रा नदी हर हाल में हो जाए पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त

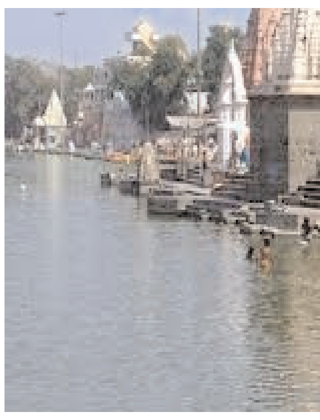

भोपाल। मध्यप्रदेश की धार्मिक और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ मेला होना है। इसे लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। अब सरकार की ओर से सिंहस्थ-2028 के लिए होने वाले 19 कार्यों के लिए 5 हजार 882 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ को लेकर सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। वैश्विक आयोजन सिंहस्थ के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की सभी संन्यासी परंपराओं के वैष्णव और शैव संत 12 साल में सिंहस्थ में आते हैं और भविष्य में सनातन धर्म की दिशा, आचरण और स्वरूप तय करते हैं। मानवता की स्थापना के लिए सिंहस्थ मेला 2028 में फिर से आयोजित होने वाला है। इसकी तैयारियां अभी से प्रारंभ हो चुकी हैं। सीएम यादव ने कहा कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकाल लोक और दूसरे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। प्रदेश की पहचान धार्मिक नगरी उज्जयिनी में हर 12 वर्ष में होने वाले सिंहस्थ के रूप में होती है। ऐसे में सिंहस्थ प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। पूरे विश्व में इसकी गूंज होती है। सीएम ने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए नए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।

**15 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना** सीएम यादव ने कहा कि सिंहस्थ को सफल बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करनी होंगी। इन सभी कार्यों को शासकीय विभागों और अन्य उपक्रमों के तालमेल के साथ पूरा करने के लिए जुटना होगा। ऐसी योजना तैयार की जाए कि क्षिप्रा नदी हर हाल में पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो और क्षिप्रा नदी में निरंतर शुद्ध जल का प्रवाह हो। सीएम यादव ने कहा कि सिंहस्थ-महाकुंभ में दुनिया भर से करीब 15 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस वजह से उज्जैन में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।

**नए घाट बनेंगे, कान्ह नदी को लेकर भी होगा काम** कैबिनेट बैठक में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर होने वाले 19 कार्यों के लिए 5,882 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडलीय समिति ने जिन कार्यों को स्वीकृति दी है, उनमें 778 करोड़ 91 लाख रुपए के 29.21 किलोमीटर घाट निर्माण, 1,024 करोड़ 95 लाख रुपए का 30.15 किलोमीटर कान्ह नदी का डायवर्जन, 614 करोड़ 53 लाख रुपए की सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा नदी में जल निरंतर प्रवाह योजना (सिलारखेड़ी-सेवरखेड़ी बांध) का निर्माण, 74 करोड़ 67 लाख रुपए के क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित 14 बैराजों का निर्माण, 43 करोड़ 51 लाख रुपए के कान्ह नदी पर प्रस्तावित 11 बैराजों का निर्माण, 198 करोड़ रुपये से उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना, 250 करोड़ रुपए से अति. उच्च दाब से संबंधित कार्य के लिए नवीन ईएचवी उपकेंद्र का निर्माण, 16 करोड़ 80 लाख रुपए से अति. उच्च दाब केंद्र क्षमता वृद्धि का निर्माण, 29 करोड़ 83 लाख रुपए का नवीन 33/11 केवी का निर्माण, 4 करोड़ 50 लाख रुपए से 33 केवी लाइन एवं इंटर कनेक्शन और नवीन उपकेंद्र से संबंधित कार्य (10 किलोमीटर), 18 करोड़ 36 लाख रुपए से केवी लाइन एवं इंटर कनेक्शन और नवीन उपकेंद्र से संबंधित (80 किलोमीटर) का निर्माण और 10 करोड़ 8 लाख रुपए का भूमिगत केबल कार्य (ओंकारेश्वर बजट) का निर्माण शामिल है।

**ये काम भी किए जाएंगे-** इसी तरह 18 करोड़ रुपये का शंकराचार्य चौराहा से दत्त अखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से उज्जैन-बड़नगर मार्ग का निर्माण, 18 करोड़ रुपये का खाक चौक, वीर सावरकर चौराहा, गढ़कालिका, भर्तहरी गुफा से रंजीत हनुमान तक मार्ग और क्षिप्रा नदी पर पुल का निर्माण, 40 करोड़ रुपये से सिद्धवरकूट से कैलाश खोह तक सस्पेंशन ब्रिज पहुंच मार्ग प्रोटेक्शन कार्य सहित (ओंकारेश्वर में कावेरी नदी पर पैदल पुल सहित ओंकारेश्वर घाट से सिद्धवरकूट तक पहुंच मार्ग का निर्माण), 1692 करोड़ रुपये से इंदौर-उज्जैन विद्यमान 4 लेन मार्ग का 6 लेन मय पेव्ड शोल्डर में हाईब्रिड एन्युटी मॉडल अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण, 950 करोड़ रुपये से इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण कार्य, 75 करोड़ रुपये से महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थित फाइबर की प्रतिमाओं के स्थान पर पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापना, आवश्यक विकास कार्य और कुंभ संग्रहालय, काल गणना शोध केंद्र उज्जैन का अनुरक्षण और विकास कार्य शामिल है।

**18 विभागों के 568 कार्यों के प्रस्ताव मिले** अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास नीरज मंडलोई ने बताया कि अभी तक सिंहस्थ-2028 के लिए 18 विभागों के 568 कार्यों के प्रस्ताव मिले हैं, जिनकी अनुमानित लागत 15,567 करोड़ रुपये है। इन कार्यों में विभागीय, सिंहस्थ मद और बीओटी आदि के कार्य शामिल हैं। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि इंदौर में लव-कुश चौराहे से उज्जैन तक नवीन मेट्रो लाइन बिछाए जाने का सर्वेक्षण कार्य दिल्ली रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है।

## पुलिस भर्ती में 'घोटाला' रोकने 'थियोडोलाइट' का इस्तेमाल कर रही सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नहीं चाहते कि युवाओं के भविष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ हो। इसके कारण पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया है।

वर्तमान में पुलिस आरक्षक के 7500 पदों के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना खत्म हो सके। मध्यप्रदेश पुलिस थियोडोलाइट यंत्र का उपयोग कर रही है। इसकी खास बात यह है कि इससे आंकड़े बिल्कुल सही आते हैं। आपको बता दें कि प्रदेशभर में 54 हजार अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबी कूद और गोला फेंक में माप के लिए 'थियोडोलाइट' तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जहां पर गोला गिरता है वहां प्रिज्म लेजर रखकर इसके माध्यम से उसका मापन थियोडोलाइट से किया जा रहा है। इस मशीन की रीडिंग अभ्यर्थी के रोल नंबर के साथ ही सीधे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है। ऐसे में रीडिंग की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बता दें कि थियोडोलाइट एक ऐसी मशीन है, जिसे आमतौर पर सिविल इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए किया जाता है। इससे माप में पूरी शुद्धता रहती है। गौरतलब है कि प्रदेश में पुलिस आरक्षकों के लगभग साढ़े सात हजार पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा बुधवार से प्रारंभ हो गई है। इस भर्ती में प्रदेश के 10 जिलों में केंद्रों में 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक की परीक्षा ली जा रही है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के 100 अंक रखे गए हैं। इतने ही अंकों की लिखित परीक्षा पहले हो चुकी है। दोनों को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

## बाल विवाह निषेध कानून को नहीं रोक सकते 'पर्सनल लॉ'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बाल विवाह के खिलाफ बने कानून को पर्नसल लॉ के जरिये बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह, जीवन साथी अपनी इच्छा से चुनने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की सदस्यता वाली पीठ ने बाल विवाह रोकने के लिए बने कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। अपने फैसले में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए बने बाल विवाह निषेध कानून को पर्सनल कानूनों के जरिये बाधित या रोका नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि अधिकारियों को बाल विवाह रोकने और नाबालिगों की सुरक्षा के साथ ही दोषियों को कड़ी सजा दिलाने पर फोकस करना चाहिए। अपने फैसले में पीठ ने यह भी माना कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए समाज में जागरुकता फैलाने की जरूरत और सिर्फ सजा का प्रावधान करने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी फॉर एनलाइनमेंट एंड वॉलेंटरी एक्शन की याचिका पर यह फैसला सुनाया। एनजीओ का आरोप था कि बाल विवाह निषेध कानून को शब्दश- लागू नहीं किया जा रहा है। एनजीओ ने साल 2017 में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है।

बता दें कि बाल विवाह निषेध कानून, 2006 देश में बाल विवाह रोकने के लिए लागू किया गया था। साल 1929 में यानी कि आजादी से पहले से देश में ये कानून मौजूद है। साल 2006 में तत्कालीन सरकार ने इस कानून में बदलाव कर बाल विवाह निषेध कानून 2006 लागू किया। पीठ ने कहा कि ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि अलग-अलग समुदायों के लिए कानून में लचीलापन मौजूद रहे।

आवश्यकता

प्रदेशो, जिला एवं तहसील स्तर पर एक कंपनी के लिए मार्केटिंग हेतु युवक / युवतियों की योग्यता 10वीं से ग्रेजुएट

वेतन 15 हज़ार - 20 हज़ार होगा आगे योग्यता अनुसार

Contact WhatsApp Only, Text Message :
9755996590

**आबोहवा बचाने की जद्दोजहद: पेड़ों की कटाई के विरोध में पर्यावरण प्रेमी सड़क पर उतरे, शांतिपूर्वक किया प्रदर्शन**

# इंदौर की बंद पड़ी कपड़ा मिलों को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाए...

**सिटी चीफ इंदौर।**

इंदौर। इंदौर की मिलों को सिटी फॉरेस्ट घोषित करने के लिए शुक्रवार को इंदौर के पर्यावरण प्रेमियों ने रीगल तिराहे पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शहर के अलग-अलग वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए और सभी ने इस विषय पर एकमत होकर राय दी की इंदौर में सभी मिलों को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाना चाहिए। शांतिपूर्वक हुए इस प्रदर्शन में अजय लागू, एसएल गर्ग, अरविंद पोरवाल, संदीप खानवलकर, प्रमोद नामदेव, राहुल निहोरे, अशोक दुबे आदि शामिल हुए। सभी ने शांतिपूर्ण हुए इस प्रदर्शन के बाद में रीगल से संभाग आयुक्त कार्यालय तक पैदल जाकर कमिश्नर दीपक सिंह को ज्ञापन दिया और यह निवेदन किया कि शहर की हरियाली को बचाया जाए, पेड़ों की कटाई को बंद किया जाए और शहर की मिलों की हरियाली को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाए। आंदोलन कर रहे पर्यावरण प्रेमी नागरिक मंच के सदस्यों ने बताया कि इंदौर शहर एक समय अपनी हरियाली एवं बाग-बगीचों के कारण जाना जाता था। नौलखा क्षेत्र में नौलाख पेड़ थे। शहर के कई क्षेत्र आज भी पेड़ों के नाम से ही जाने जाते हैं, जैसे खजूरी बाजार, इमली बाजार, मोरसली गली, बड़ वाली चौकी, पलासिया, लाल बाग, बियाबानी आदि। आज कई बाग काट दिए गए और कई कटने की राह पर हैं।

**मिलों के सघन पेड़ों ने बचाया है भूमिगत जल**

पर्यावरण प्रेमी श्याम सुंदर यादव ने कहा कि वायु गुणवता को सुधारने में पेड़ों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शहर के मध्य क्षेत्र में बंद पड़ी कपड़ा मिलों में प्राकृतिक रूप से निर्मित शहरी वन (सिटी फॉरेस्ट) के कारण न सिर्फ शहर की आबोहवा ज्यादा खराब होने से बची हुई है, वरन सघन पेड़ों के कारण भूमिगत जल का स्तर भी खतरनाक स्तर तक घटने से बचा हुआ है। अत: शहर के लिए ऐसे अनमोल दिल एवं हरे-फेफड़ों का संरक्षण अत्यंत जरुरी है।

**हुकुमचंद मिल परिसर में लगे हैं 2000 से अधिक पेड़: पर्यावरण प्रेमी एसएल गर्ग ने कहा कि अब** ज्यादा से ज्यादा पुराने पेड़ बचाए जाना ही अंतिम विकल्प है। इसलिए विकास की आगामी योजनाएं इस प्रकार बनाई जाएं कि अधिक से अधिक पेड़ों का संरक्षण हो सके। वर्तमान में एक आसन्न संकट हुकुमचंद मिल परिसर में लगे 2000 से अधिक पेड़ों पर है। यह पेड़ न केवल शुद्ध हवा देते हैं अपितु कार्बन संचयन भी कर रहे है। यह शहरी वन सालाना बहुमूल्य कार्बन क्रेडिट भी उत्पन्न कर रहे हैं। जहां हाउसिंग बोर्ड की रिहायशी एवं व्यावसायिक काम्प्लेक्स बनाने की योजना है। पर्यावरण प्रेमी अशोक दुबे ने कहा कि अत: यहां सिटी फॉरेस्ट घोषित किया जाए और शहरहित में निर्णय लिया जाए। साथ ही सभी बन्द मिल परिसरों को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने के प्रयास करने का विनम्र अनुरोध है।

**30% से घटकर 9-10% रह गई हरियाली**

पर्यावरण प्रेमी संदीप खानवलकर ने बताया कि 70 के दशक में शहरी क्षेत्र में 30% हरियाली थी, जो वर्तमान में 9-10% के लगभग है)। वर्ष 2023 में शहर का ग्रीन इंडेक्स भी मात्र 09 बताया गया है। पिछले मास्टर प्लान (2008 से 2021) में हरियाली का विकास 22% तक होना बताया गया था, परंतु वह भी 9 या 10% पर ही रह गया है। अरविंद पोरवाल ने कहा कि दीर्घजीवी होने के कारण हरियाली में सबसे ज्यादा महत्व पेड़ों का होता है। वर्तमान में शहर में 10 लाख के लगभग पेड़ बताए गए हैं, जबकि पंजीकृत वाहन 31 लाख से ज्यादा एवं जनसंख्या भी 34 लाख से अधिक है।

**पांच साल में 1.50 लाख से ज्यादा पेड़ काटे**

आईआईटी, इंदौर के एक अध्ययन के अनुसार शहर में पिछले पांच वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 1.50 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए। हरियाली घटने, विशेषकर पेड़ कम होने से शहर का तापमान बढ़ रहा है एवं वायु गुणवत्ता में भी इतने प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। पर्यावरण प्रेमी ओपी जोशी ने बताया कि एक आकलन के अनुसार वर्ष 2019 के बाद लू (हीट वेव) के दिन 19 से बढ़कर 25 हो गए एवं मई में 40 डिग्री सें. तापमान के दिन भी 10 से बढ़कर 15 हो गए हैं। मई 2024 में 11 दिन तापमान 40 डिग्री सें. से ऊपर रहा एवं 23 मई को 44.5 डिग्री सें. ऊपर पहुंच गया। कुछ दिनों रात का तापमान भी राजस्थान के जयपुर एवं चुरु से ज्यादा रहा।

**विभागों में आपसी समन्वय नहीं होने से समय पर नहीं भरे जा रहे**

# महापौर परिषद बैठक में छाया रहा सड़कों पर गड्ढों का मुद्दा

**सिटी चीफ इंदौर।**

इंदौर में जगह-जगह सड़कों पर होने वाले गड्ढों का मुद्दा शुक्रवार को महापौर परिषद बैठक में छाया। महापौर परिषद सदस्यों ने कहा कि गड्ढों के कारण ट्रैफिक बाधित हो रहा है। विभागों में आपसी समन्वय नहीं होने से गड्ढे समय पर नहीं भरे जाते है और इस कारण ट्रैफिक भी खराब हो रहा है। बैठक में नक्शे मंजूर न होने, पार्किंग व अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। चार घंटे चली महापौर परिषद बैठक में महापौर परिषद सदस्य जीतू यादव बोले कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के कारण शहर में जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं। लोगों को नहीं पता रहता कि किस विभाग ने गड्ढे खोदे है। वे नगर निगम को जानते हैं। निगम के विभागों में तालमेल नहीं है। नर्मदा पाइप का रिसाव खोजने के लिए जगह-जगह गड्ढे खोद दिए जाते हैं और फिर उन्हें समय पर नहीं भरा जाता। इससे ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। गड्ढों को प्राथमिकता से भरा जाना चाहिए। मेयर ने कहा कि हम एक एजेंसी तय कर देते हैं, जो तत्काल सड़कों के गड्ढे भरे। इससे राहत मिलेगी। बैठक में महापौर परिषद सदस्य मनीष शर्मा ने कहा कि बैनर, पोस्टर हटाने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के बैनर, पोस्टर नहीं हटते, तो कुछ के लगाते ही हटा दिए जाते हैं। बैठक में कुछ इलाकों के नक्शे मंजूर नहीं होने का मुद्दा भी उठा।

**500 करोड़ के काम होंगे 29 गांवों में**

मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने बताया कि नगर निगम में शामिल शहर के 29 गांवों के कई इलाकों में सीवरेज लाइन नहीं बिछाई गई है। इसके अलावा नर्मदा लाइन भी नहीं है। उन इलाकों में 500 करोड़ रुपए के काम इस साल शुरू होंगे। इसके अलावा शहर के चार मल्टी लेवल पार्किंग की छतों पर बच्चों के लिए झूले-चक्करी और फूड जोन बनाए जाएंगे। भार्गव ने बताया कि नगर निगम का नया पोर्टल भी सप्ताह भर में शुरू होने जा रहा है।

**रेसीडेंसी कोठी का नया नाम शिवाजी वाटिका होगा**

महापौर ने बताया कि शहर की रेसीडेंसी कोठी का नया नाम शिवाजी वाटिका होगा। मल्टी लेवल रूफटॉप पर प्ले जोन बनाए जाएंगे। शहर में बचे स्थानों पर जीआईएस सर्वे कराया जाएगा। ब्रिज और फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे हॉकर्स जोन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी। संजीवनी क्लीनिक को एनजीओ के माध्यम से संचालन किया जाएगा।

**इन प्रस्तावों पर लगी मुहर**

-महापौर परिषद बैठक में तय हुआ कि अमृत प्रोजेक्ट के अगले काम के लिए 800 करोड़ के टेंडर, वर्कशॉप विभाग को डिजिटल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण।

- टंटया भील भंवरकुंआ चौराहा, फूटी कोठी, खजराना चौराहा व केसरबाग फ्लाई ओवर के नीचे हॉकर्स जोन, स्पोर्टस एक्टिविटी संचालित होंगे।

-निगम का पोर्टल डेवलप किया जाएगा। ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए खराब और लावारिस वाहन जिनके कारण सफाई नहीं होने से कचरा इकट्ठा होता है, हटाया जाएगा। इस संबंध में बायलास बनाया जाएगा।

-सभी वार्डों में चार पैकेज के माध्यम से सीवर लाइन और चैंबर सफाई के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से टास्क फोर्स का गठन होगा।

**पांच सड़कें होगी ठेला मुक्त**

महापौर परिषद बैठक में तय हुआ कि शहर की 5 प्रमुख सडकों को ठेला मुक्त किया जाएगा। प्रमुख स्थानों और बाजारों को बिजली तारों के जाल से भी मुक्त किया जाएगा। जन सुविधा के लिए फूट ओवर ब्रिज का निर्माण, राजस्व वसूली के दौरान चेक बाउंस होने पर अर्थ दंड, वार्ड एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति होगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य संस्था नवीन मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक को सामाजिक संगठन के माध्यम से संचालन करने के लिए एमओयू को मंजूरी दी गई। रीजनल पार्क में पीपीपी मॉडल पर एम्युमेंट पार्क का डेवलपमेंट, जू में भी पीपीपी मॉडल आधार पर 14 डी सिनेमा थियेटर व वर्चुअल जंगल सफारी का निर्माण होगा। इसके 15 तक के संचालन के लिए टेंडर जारी होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न परिसरों में बहुमंजिला आवासीय इकाइयों के आवंदन में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी में विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों की सूची अनुमोदन, विभिन्न चौराहों व उद्यानों के नामकरण की मंजूरी दी गई।

# एक लाख की घूस लेते पकड़ाई शिक्षा विभाग की समन्वयक

**सिटी चीफ इंदौर।**

इंदौर। इंदौर लोकायुक्त ने शुक्रवार को जिला परियोजना समन्वयक शीला मेरावी को एक लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ट्रेजर टाउन बीजलपुर के दिलीप बुधानी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। शीला मेरावी ने स्कूल संचालक दिलीप बुधानी से उनके दो स्कूलों की मान्यता रद्द करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की थी। लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय ने बताया कि दिलीप बुधानी निवासी ट्रेजर टॉउन बिजलपुर ने इसकी शिकायत थी। इसमें बताया कि वे एमपी पब्लिक स्कूल अशोक नगर और एमपी किड्स स्कूल अंजली नगर के संचालक हैं। दोनों ही स्कूल शासन से मान्यता प्राप्त हैं। इसमें वर्ष 2019-20 से 23-24 तक मान्यता के साथ स्टूडेंट्स को 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल कराया गया था।

इसमें वर्ष 2019-20 से 23-24 तक मान्यता के साथ स्टूडेंट्स को 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल कराया गया था। आरोप है कि आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा ने जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र इंदौर से सूचना के अधिकार तहत दोनों स्कूलों के छात्र/छात्राओं की 5वी और 8वीं की परीक्षा में शामिल होने के संबंध में जानकारी मांगी थी। वह स्कूल संचालक दिलीप बुधानी को ब्लैकमेल कर रहा था कि दोनों स्कूलों की मान्यता समाप्त करा देगा। इस पर जिला परियोजना समन्वयक शीला मेरावी जांच नहीं कराने और आगे भी आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा कोई शिकायत नहीं करेगा, ऐसा लिखवाकर देने के एवज में 10 लाख रुपए मांग रही थी। बाद में ये 4 लाख रुपए तय हुआ था। इसकी पहली किस्त एक लाख रुपए शुक्रवार को दी गई थी। तभी लोकायुक्त की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

**पार्किंग में ली रिश्वत की पहली किस्त**

शुक्रवार शाम को दिलीप बुझानी रिश्वत की एक लाख रुपए की पहली किस्त लेकर शीला मेरावी के राजेंद्र नगर ब्रिज के पास स्थित कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने मेरावी को ऑफिस के पार्किंग एरिया में एक लाख रुपए दिए। जिसे मेरावी ने अपने वाहन में रख लिए। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने उन्हें पकड़ लिया। शीला मेरावी के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया गया है।

# रातभर टैंकरों की आवाजाही से लोग परेशान, निगम ने सील का बोरिंग

**सिटी चीफ इंदौर।**

एयरपोर्ट इलाके में नगर निगम ने एक प्राइवेट बोरिंग को सील किया है। कॉलोनी में रातभर बोरिंग चलने और टैंकरों की आवाजाही से लोग परेशान थे। रहवासियों द्वारा निगम अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की गई थी। जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जोन 16 के तहत आने वाले वार्ड 15 के शक्ति नगर में शिव मंदिर के पास रूपेश गोस्वामी नामक व्यक्ति द्वारा निजी बोरिंग से पानी निकालकर टैंकरों में भरकर इसे बेचा जाता है। इस संबंध में शक्ति नगर, बाबू मुराई कालोनी और पटेल नगर के रहवासियों द्वारा गोस्वामी के टैंकर का वीडियो बना कर अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा को भेजा गया था और शिकायत की गई। अपर आयुक्त ने खुद टीम भेजी और वीडियो ग्राफी करवाई तो टैंकर भरा हुआ मिला। नगर निगम ने गोस्वामी को नोटिस भी जारी किए, लेकिन इसके बावजूद पानी की बरबादी बंद नहीं हुई। गुरुवार को अपर आयुक्त मिश्रा के निर्देश पर निगम के जल यंत्रालय विभाग के सहायक यंत्री ब्रिजमोहन भगोरिया, उपयंत्री प्रिंस कुमार, जोनल अधिकारी दीपक गरगटे के साथ मौके पर पहुंची और मोटर, केबल जब्त करने के साथ-साथ बोरिंग सील करने की कार्रवाई की। शक्ति नगर के रहवासियों के अनुसार बोरिंग से रातभर मोटर चलाकर पानी निकाला जाता था।

# प्रॉपर्टी व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

**सिटी चीफ इंदौर।**

**इंदौर।** इंदौर की परदेशीपुरा के कलश चौराहे के पास प्रॉपर्टी व्यवसायी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को बदमाश सूरज जाट और उसके 2 साथियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। घटना गुरुवार रात की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हत्या करने की नीयत से यहां पहुंचे थे। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू की गई है। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि परदेशीपुरा में रहने वाले प्रॉपर्टी व्यवसायी रिंकू ठाकुर ने थाने आकर शिकायत की थी कि वह रखोडी सेठ की धर्मशाला के यहां पर खड़ा थे। इस दौरान पंचवटी निवासी सूरज जाट,आशीष पाल और उसका साथी अभिषेक ताहिर आया। उन्होंने धमकाया और घूरने की बात पर अपशब्द कहे। इसके बाद चाकू निकालकर हमला किया। जिसमें रिंकू ने जान बचाई। आशीष ने दूसरा चाकू निकालकर फिर से घुमाया तो झुककर नीचे गिर गया। इस दौरान आरोपियों ने वहां सड़क पर मारपीट कर दी। इस दौरान रिंकू के परिचित भी वहां पहुंच गए।

# शिमला जैसा होगा दक्षिणी मध्यप्रदेश का मौसम

**इंदौर।** मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मध्यप्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में अगले चार दिनों तक बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इंदौर में शुक्रवार को दिनभर बादल और धुंद छाई रही। दिन और रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य था, और न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य औसत से 2 डिग्री सेल्सियस विचलन दर्शाता है।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा, सुबह के समय धुंध छाई रही। अरब सागर के ऊपर बना सिस्टम कमजोर हो गया है, जिससे इंदौर में बारिश से कुछ समय के लिए राहत मिली है। इसके अलावा, पश्चिमी विक्षोभ जो आमतौर पर तापमान को प्रभावित करते हैं, वे भी खत्म हो गए हैं, जिससे आगे रातें ठंडी होंगी। पिछले एक दशक में, ठंड की शुरूआत आमतौर पर 15 अक्टूबर के बाद देखी जाती थी। इन दिनों सुबह में धूप खिली रहती है, जिसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट आती है, और रात 9 बजे के आसपास ठंड का अहसास होता है। इस सप्ताह, शहर में आधे इंच से अधिक बारिश हुई। लेकिन फिलहाल आसमान साफ है।

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 19-20 अक्टूबर को हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। 21 अक्टूबर से एक और सिस्टम के कारण बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन इसका मालवा क्षेत्र पर कम असर होने की उम्मीद है। गुरुवार को खरगोन जिले में सुबह कोहरे के कारण दृश्यता लगभग 20 मीटर तक गिर गई, जिससे वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी। शहरी क्षेत्रों में कोहरा कम रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खासा असर रहा।

# फैजान के साथ पकड़ी गई युवतियों से पता चलेगा देह व्यापार में कैसे धकेली गईं

**सिटी चीफ इंदौर।**

इंदौर। इंदौर के लसूडिया इलाके में गुरुवार रात को पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मारकर कई युवक-युवतियों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा। इस छापेमारी में पुलिस ने फैजान उर्फ गोल्डी नामक मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके मोबाइल से कई अश्लील वीडियो, चैट्स और एक डायरी मिली, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज थे। पुलिस को शक है कि फैजान लंबे समय से देह व्यापार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में संलिप्त था। यह

कार्रवाई हिंदूवादी जागरण मंच के कार्यकताओं की सूचना के बाद की गई। संगठन के जिला संयोजक राजकुमार टैटवाल और मानसिंह राजावत ने आरोप लगाया कि फैजान कई युवतियों को बंधक बनाकर उनसे देह व्यापार करा रहा था। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और फ्लैट पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फ्लैट से कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद कीं, जिनमें नकली पिस्टल, लाइटर के रूप में दिखने वाली रिवॉल्वर, तलवार और अन्य संदिग्ध वस्तुएं शामिल थीं। पुलिस को फैजान के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले, जिनमें से कुछ वीडियो में युवतियों को जबरन शराब पिलाकर डांस कराने और गांजे का नशा करवाने के दृश्य भी देखे गए। इसके अलावा, फैजान की चैटिंग में ब्रोकरों से बातचीत के दौरान लड़कियों की फोटो शेयर करने और सौदेबाजी की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस को कुछ ऐसे वीडियो भी मिले हैं, जिनमें फैजान ब्रोकरों के साथ सौदेबाजी कर रहा था।

**देह व्यापार का मामला**

डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि फैजान पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जा रही है। एडीशनल डीसीपी अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि फैजान के मोबाइल में मिली सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि वह देह व्यापार में सक्रिय रूप से लिप्त था और उसका नेटवर्क काफी बड़ा था। पुलिस को शक है कि यह मामला केवल देह व्यापार का नहीं, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हो सकता है। इसी दिशा में पुलिस अब जांच कर रही है।

**देवास का रहने वाला है फैजान**

फैजान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके अन्य संपर्कों की भी जांच शुरू कर दी है। उसके मोबाइल में मिले 200 से ज्यादा नंबरों की जांच की जा रही है, ताकि पता चल सके कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

हिंदू जागरण मंच के आरोपों के अनुसार, फैजान युवतियों को जबरन देह व्यापार में धकेलता था और उन्हें बंधक बनाकर रखता था। यह भी पता चला है कि फैजान मूल रूप से देवास का रहने वाला है और पिछले एक साल से इंदौर में रह रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने फैजान से गहन पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों का खुलासा हो सके।

## सिंगल कॉलम

### मीटिंग से अफसर गायब, भड़के सभापति और भोपाल जिला पंचायत सदस्य

**भोपाल।** भोपाल जिला पंचायत में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास स्थाई समिति की मीटिंग हुई। इसमें विभाग के जिला अधिकारी सुनील सोलंकी ही गायब रहे। इस पर समिति सभापति और जिपं सदस्य चंद्रेश राजपूत समेत अन्य सदस्य भड़क गए। उन्होंने सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर और सीईओ से मिलने की बात भी कही। मीटिंग में बताया गया कि सोलंकी दो साल से मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। बैठक में समिति सचिव सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने एजेंडा रखा। इसी दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी सोलंकी के मौजूद नहीं रहने पर सभी सदस्य नाराज हो गए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी सदस्यों ने कही है। सभापति राजपूत ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी की स्थिति ठीक नहीं है। भवनों में साफ-सफाई के साथ पुताई एवं मरम्मत कार्य भी नहीं किए गए हैं। बैठक में मौजूद सुपरवाइजर से कहा गया कि जल्द ही भवनों की रंगाई-पुताई की जाए। सभापति राजपूत ने कहा कि मेरे दौरे के दौरान किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर लापरवाही मिलती है तो में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करुंगी। बैठक में पीएचई विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिपं उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट, सदस्य रश्मि भार्गव, प्रतिनिधि अनिल हाड़ा, मिश्रीलाल मालवीय, जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनोज हुरमाणी बैरसिया आदि भी मौजूद थे।

### मप्र के मौसम, सौर ऊर्जा पर एक्सपर्ट ने किया मंथन, दो साल में बनेगा प्लान

**भोपाल।** मध्यप्रदेश के क्लाइमेंट यानी, मौसम पर शुक्रवार को भोपाल में एक्सपर्ट ने मंथन किया। सबसे खास सौर ऊर्जा पर फोकस रहा। दिल्ली मेट्रो और रीवा सौलर प्लांट के उदाहरण दिए गए। अब दो साल में प्लान बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा। ताकि, नीतिगत बदलाव किए जाए। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) ने डब्ल्यूआरआई इंडिया के सहयोग से मध्यप्रदेश की दीर्घकालिक न्यून कार्बन विकास रणनीति विकसित करने के लिए भोपाल में सेमिनार किया। साल 2026 तक विकसित की जाने वाली इस रणनीति का उद्देश्य भारत के 2070 के नेट जोरो के टारगेट में योगदान देना है। ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा- दीर्घकालिक न्यून कार्बन विकास रणनीतियां केवल एक महत्वपूर्ण कदम ही नहीं बल्कि बिजनेस अस यूजुअल परिदृश्य की तुलना में लंबे समय में अधिक लाभदायक साबित हो रही हैं। उन्होंने रीवा में सौर ऊर्जा प्लांट का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह दूरदर्शी दीर्घकालिक न्यून कार्बन रणनीति राज्य के लिए हरित विकास, अधिक लाभ और बचत की ओर ले जा रही है। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो के मामले में 60त्न ऊर्जा की जरूरतें (दिन के समय) सौर संयंत्र से पूरी की जाती है। जिससे सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत होती है।एप्को की कार्यपालन संचालक डॉ. सलोनी सिदाना ने कहा कि, मध्यप्रदेश भारत में छठे सबसे अधिक जीएचजी उत्सर्जक राज्य के रूप में उभर कर आया है। जहां प्रति व्यक्ति उत्सर्जन राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

### रानी कमलापति स्टेशन के पास एम्स के आउटसोर्स कर्मचारी ने दी जान

**भोपाल।** रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के आउटर के पास पटरी किनारे एम्स भोपाल के एक आउटसोर्स कर्मचारी का शव बरामद किया गया। शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत था। मृतक की पहचान दीपक महोबे (27) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बैतूल का रहने वाला था। वह एम्स भोपाल में 16 जून 2024 से एक आउटसोर्स कंपनी के जरिए कार्यरत था। पुलिस के अनुसार, दीपक का धड़ मिला, लेकिन सिर घटनास्थल पर नहीं था। मौके पर मिले मोबाइल फोन से उसकी पहचान की गई। बागसेवनिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, दीपक बरखेड़ा इलाके में अपने मामा के घर पर रहता था। मंगलवार रात खाना खाने के बाद दीपक कब घर से निकला, इसका किसी को पता नहीं चला। बुधवार तड़के एक लोको पायलट ने रेलवे कंट्रोल रूम को रानी कमलापति आउटर के पास किसी व्यक्ति के ट्रेन से टकराने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शुरूआत में कुछ नहीं मिला। बाद में, बताए गए स्थान से लगभग एक किलोमीटर दूर दीपक का शव बरामद हुआ। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दीपक ने आत्महत्या की है या यह किसी अन्य कारण से हुआ हादसा है।

# कृषि मंत्री कंषाना बोले- प्रदेश में खाद की कमी नहीं, विपक्ष फैला रहा भ्रम

**सिटी चीफ भोपाल।**

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों के बीच खाद संकट के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयानों के जवाब में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने शुक्रवार को पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और विपक्षी नेता किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। श्यामला हिल्स स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि हमने खरीफ के सीजन में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार किसानों की जरूरतों के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे। विपक्षी पार्टी जानबूझकर किसानों को गलत जानकारी देकर भ्रम फैला रही है। विपक्षी पार्टी द्वारा किसानों भ्रमित जानकारी दी जा रही है। इस साल अंतरराज्यीय बाजार में डीएपी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का कारण यूक्रेन और इजराइल का युद्ध है। इनके संघर्ष के कारण आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि मध्यप्रदेश में खाद संकट के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय (1993-2003) में खाद की कोई कमी नहीं थी और न ही कोई कालाबाजारी हुई थी, जबकि आज खाद की ब्लैक मार्केटिंग और नकली खाद के मामले सामने आ रहे हैं।

मंत्री कंषाना ने बताया कि खरीफ 2024 में 32.97 लाख मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले 33.69 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। इसी तरह, रबी 2024 के लिए 41.10 लाख मीट्रिक टन की मांग के विरुद्ध 19 लाख मीट्रिक टन उर्वरक अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है। इनमें 7.74 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.21 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 6.05 लाख मीट्रिक टन एसएसपी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अग्रिम भंडारण की नीति अपनाता है, ताकि किसी भी समय किसानों को उर्वरकों की कमी का सामना न करना पड़े। इस वर्ष रबी सीजन की शुरूआत में राज्य ने पहले ही 6.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अग्रिम भंडारण कर लिया था। भारत सरकार से भी राज्य को पर्याप्त उर्वरक मिल रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा।

**उर्वरकों की गुणवत्ता पर खास ध्यान**

मंत्री कंषाना ने यह भी कहा कि सरकार उर्वरकों की गुणवत्ता पर खास ध्यान दे रही है। यदि कहीं भी घटिया गुणवत्ता के उर्वरक, बीज, या कीटनाशक बेचे जाने की सूचना मिलती है, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। मंत्री कंषाना ने कहा कि किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों को उपयोग करने की सलाह दी गई है। फूल आने से पहले स्प्रे करने से उपज में वृद्धि होती है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री पर अन्य उर्वरक टैग करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दिए गए उर्वरक अच्छी क्वालिटी के हों। जहां भी घटिया क्वालिटी के उर्वरक और कीटनाशक किसानों को दिए जाएंगे उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कालाबाजारी और नकली उर्वरकों के मामले में हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे।

**किसान वैज्ञानिकों की सलाह मानेंगे न कि, विपक्ष की**

मंत्री कंषाना ने यह भी कहा कि विपक्षियों का यह कहना गलत है कि उर्वरकों की कमी है हम किसानों को योग्य वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उर्वरक प्रदान कर रहे हैं। किसान वैज्ञानिकों की सलाह पर अधिक भरोसा करेंगे न कि विपक्ष के नेताओं की झूठी बातों परङ्क. मेरी विपक्ष को भी यह सलाह है कि किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आपको आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा किसी के झूठे बयानों के शिकार ना हों।

दिग्विजय को आरोप लगाने की आदत

पूर्व सीएम के आरोपों पर कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा- दिग्विजय सिंह की तो आदत बन गई है आरोप लगाना। उन्होंने जब-जब हमारी सरकार पर आरोप लगाए तब-तब जनता ने उनको आड़े हाथों लिया। चाहे विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के चुनाव हों। चाहे हरियाणा के चुनाव हो जहां-जहां वे झूठे आरोप लगाते हैं जनता इसका बाकायदा जवाब दे रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की किसानों को गलत जानकारी ना दें किस को भ्रमित ना करें। यह लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि डीएपी के बगैर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है डीएपी के बगैर अन्य और भी खाद है उनकी वजह से हमारी फसल और अच्छी हो सकती है।

गड़बड़ी के सबूत दें तो कार्रवाई करेंगे।

कंषाना ने कहा कि रहा सवाल आरोप-प्रत्यारोप का तो उनके पास कोई ठोस सबूत हों तो हमारे पास लाए, कहां कालाबाजारी हो रही है? वे कहीं कह रहे हैं कि समिति में गड़बड़ी हो रही है, कहीं कह रहे हैं कि खाद- बीज में हो रहा है। ऐसी हवा में लाठी मार रहे हैं। कहीं हो रहा है तो हमें बताओ कि इस जगह कालाबाजारी हो रही है हम छापा डलवाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

# सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता सुधार पर आज होगा मंथन

## केंद्रीय मंत्री गडकरी और विशेषज्ञ करेंगे विचार-विमर्श

**सिटी चीफ भोपाल।**

भोपाल। सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता में सुधार और नई तकनीकों के उपयोग से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन शनिवार और रविवार को भोपाल के रवींद्र भवन में होगा। इस सेमिनार का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) और मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। मध्यप्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेमिनार में सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक मंच पर आकर अपने अनुभव और नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत और प्रभावी बनाना है।

**विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव प्रस्तुत करेंगे**

सेमिनार में सड़क और पुल निर्माण के लिए नई तकनीक, नई सामग्रियों का उपयोग और अनुबंध प्रक्रिया (ईपीसी- इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) से जुड़ी चुनौतियों पर विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव प्रस्तुत करेंगे। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ संरचनाओं का निर्माण नहीं है, बल्कि ऐसी परियोजनाओं का विकास करना है जो समाज के सतत विकास में योगदान दे सकें। हमारा लक्ष्य भविष्य की सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से और कम लागत में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना है।

सेमिनार का उद्घाटन 19 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह करेंगे। इसके बाद तकनीकी सत्रों में देशभर के विशेषज्ञ नई निर्माण तकनीकों, सामग्रियों और ईपीसी प्रक्रिया पर अपने विचार साझा करेंगे।

**आज इस विषय पर होगी चर्चा**

शनिवार, 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई तकनीकों का उपयोग, पुल निर्माण में नई मशीनरी का उपयोग और सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सड़क सुरक्षा और परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आईटी तकनीकों के उपयोग और सीमांत सामग्रियों के बारे में भी विचार-विमर्श होगा।

**कल चुनौतियों और विवादों के समाधान पर विचार**

रविवार, 20 अक्टूबर को ईपीसी एग्रीमेंट्स की तैयारी, शेड्यूलिंग और अनुबंध प्रक्रिया से जुड़े ठेकेदारों और सहायक अभियंताओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, अनुबंधों में आने वाली चुनौतियों और विवादों के समाधान पर भी विचार किया जाएगा। इस सेमिनार का उद्देश्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और निर्माण प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशना है, ताकि आने वाली परियोजनाएं अधिक प्रभावी, टिकाऊ और समय पर पूरी हो सकें।

# भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 3589.4 करोड़ मंजूर

**सिटी चीफ भोपाल।**

भोपाल। केंद्र सरकार ने भोपाल से कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने 3589.4 करोड़ रुपए मंजूर किए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश को दी सौगात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यपेदश सरकार बढ़ती रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिख रही है। भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेडेशन से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, यातायात सुगमता के साथ ही सड़क दुर्घटना में भी कमी आयेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश में भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, सताईघाट से चौका और चौका से कैमाहा पैकेजों के लिए 3589.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस अपग्रेडेशन से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और यात्रा के समय में कमी आएगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ मंडला-नैनपुर मार्ग के लिए भी 592 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

बता दें मध्यप्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र के तहत बुंदेलखंड विकास पथ की घोषणा की थी, जो राज्य की राजधानी भोपाल को बुंदेलखंड के सागर और छतरपुर जिलों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 4-लेन सड़क परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भोपाल से सागर होते हुए छतरपुर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और यातायात सुगमता में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस मार्ग को 4-लेन में विस्तारित करने की प्रक्रिया पहले से जारी थी, लेकिन कुछ हिस्सों के लिए मंजूरी लंबित थी। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भोपाल से सागर और छतरपुर से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक इस मार्ग को 4-लेन में अपग्रेड करने की अनुमति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 3589.4 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस स्वीकृति से बुंदेलखंड विकास पथ के निर्माण में तेजी आएगी और सरकार के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जायेगी। यह पथ न केवल कनेक्टिविटी को सुधारने में सहायक होगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इसी के साथ मंडला से नैनपुर तक 46 किलोमीटर लंबे मार्ग को अपग्रेड करने के लिए भी 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग के अपग्रेड होने से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही परियोजनाओं के पूरे होने पर न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई ऊंचाई मिलेगी।

## कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर यार्ड रिमॉडलिंग

# जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी समेत 6 ट्रेनें रद्द...

**सिटी चीफ भोपाल।**

भोपाल। कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर यार्ड रिमॉडलिंग वर्क के चलते 18 से 28 अक्टूबर के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने जबलपुर मंडल की 6 प्रमुख ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों पर रद्द कर दिया है। इसके अलावा 8 अन्य ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। प्रभावित ट्रेनों में जबलपुर-सिंगरौली इंटरसिटी, सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस और निजामुद्दीन-सिंगरौली एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रद्द की गई ट्रेनों के यात्रियों को नियमानुसार टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा। इसलिए यदि आपकी यात्रा 18 से 28 अक्टूबर के बीच कटनी, जबलपुर या सिंगरौली की ओर है, तो अपनी ट्रेन की स्थिति पहले से जांच लें।

# मप्र में मुस्लिम लीग की दस्तक, 21 को भोपाल में होगा बड़ा आयोजन

**सिटी चीफ भोपाल।**

भोपाल। भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों की मजबूत मौजूदगी के बीच मप्र में में कभी तीसरे दल को पैर रखने की जगह नहीं मिल पाई। वक्त-वक्त पर इसके लिए कोशिशों का सिलसिला जरूर चलता रहा है। ऐसी ही एक दस्तक फिर सुनाई देने लगी है। दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व रखने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी (आईयूएमएल) इसी सप्ताह राजधानी में एक बड़ा आयोजन कर रही है। मजहबी मुद्दों के साथ हो रही इस शुरूआत में कई सियासी बिंदु शामिल होने वाले हैं। इसके लिए आईयूएमएल के कई बड़े नेता भोपाल आएंगे। सूत्रों का कहना है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी (आईयूएमएल) इसी माह की 21 तारीख को राजधानी भोपाल में एक बड़ा आयोजन करने वाली है। कार्यक्रम में आईयूएमएल के सांसद ईटी बशीर, राज्यसभा सांसद एडवोकेट हारिस बीरन समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम गांधी भवन में दोपहर एक से 4 बजे तक होगा।

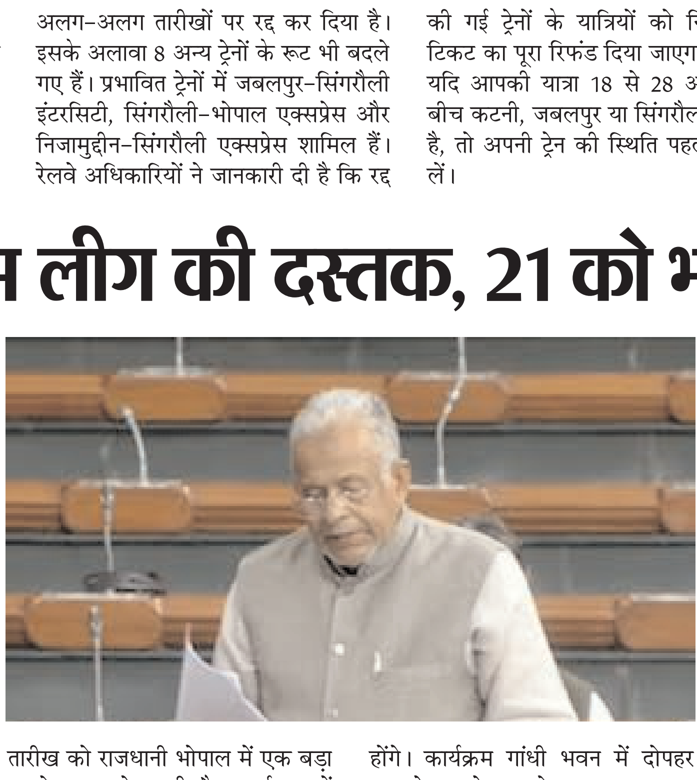

**मुद्दे कई शामिल**

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल सांसद ईटी बशीर राजधानी में होने वाले आयोजन में बात करेंगे। अमेंडमेंट बिल के खिलाफ खड़े सांसद बशीर भोपाल के आयोजन में वह बातें रखेंगे, जिनके आधार पर वे संसदीय समिति में संशोधन बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इस आयोजन के दौरान उन सभी लोगों को भी बुलाया गया है, जिन्होंने पिछले दिनों अलग अलग थानों में शिकायत कर महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। इन शिकायतों के बावजूद एफआईआर न होने को लेकर राज्यसभा सांसद एडवोकेट हारिस बीरन खास टिप्स देंगे।

**आकार ले सकती है प्रदेश टीम**

सूत्रों का कहना है कि आईयूएमएल अब मप्र में भी अपनी टीम को आकार देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में मौजूद मुस्लिम समुदाय की संख्या को देखते हुए आईयूएमएल को यहां अपने कदम जमाना आसान महसूस हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने अपने प्रदेश प्रभारियों के नाम तय कर लिए हैं, जिनके नाम राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऐलान किए जा सकते हैं।

**अभी तीसरे मोर्चा के कदम**

मप्र के आकार लेने से अब तक यहां महज दो पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ही अपनी धाक जमाए हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवाद पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियों ने भी अपनी किस्मत आजमाई।

## सम्पादकीय

# आतंकवाद के साथ संवाद, सहयोग और कारोबार नहीं चल सकते

**विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान को 'आतंकीस्तान' करार दे दिया। दुनिया जानती है कि आतंकवाद का पर्याय कौनसा देश है। 'शंघाई सहयोग संगठन' के जरिये जिस क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक मदद, आपसी कारोबार, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग, क्षेत्रीय एकजुटता आदि की अपेक्षाएं की जा रही हैं, वे आतंकवाद के रहते हुए संभव नहीं हैं, लिहाजा इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मकसद नाकाम होता है।**

आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ के साथ-साथ संवाद, सहयोग और कारोबार नहीं चल सकते। यह भारत की बुनियादी सोच है। बेशक हम पाकिस्तान के संदर्भ में यह सोच दोहराते रहे हैं, लेकिन इस बार 'शंघाई सहयोग संगठन' का मंच था, जिस पर पाकिस्तान और चीन के अलावा कुछ और राष्ट्र भी थे। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान को 'आतंकीस्तान' करार दे दिया। दुनिया जानती है कि आतंकवाद का पर्याय कौनसा देश है। 'शंघाई सहयोग संगठन' के जरिये जिस क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक मदद, आपसी कारोबार, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग, क्षेत्रीय एकजुटता आदि की अपेक्षाएं की जा रही हैं, वे आतंकवाद के रहते हुए संभव नहीं हैं, लिहाजा इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मकसद नाकाम होता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने चौतरफा विकास के लिए वास्तविक साझेदारी, शांति और स्थिरता के महत्व पर अपना पक्ष रखा। यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद जारी रहता है, तो कमोबेश देशों के बीच शांति, स्थिरता और ईमानदारी की स्थितियां बरकरार नहीं रह सकतीं। तो फिर इस संगठन का औचित्य ही क्या है? इस संगठन की स्थापना 15 जून, 2001 को चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान द्वारा शंघाई में की गई थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और भारत, पाकिस्तान, ईरान सरीखे देश जुड़ते गए। इस बार पाकिस्तान में 'शंघाई सहयोग संगठन' की शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक हुई थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की तरफ से शिरकत की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य कार्यों में व्यस्त थे। जयशंकर जैसे भाव 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने, पाकिस्तान की जमीं पर ही, व्यक्त किए थे, लेकिन इन 9 साल में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। पाकिस्तान का सीमापार आतंकवाद आज भी जारी है और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा आम सभा में पाकिस्तान के आतंकवाद का बचाव करता रहा है, लिहाजा चीन भी आतंकवाद में भागीदार है। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना को भी खारिज किया है, क्योंकि यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। यह कश्मीर भी बुनियादी तौर पर भारत का ही है। आज भी हमारे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद सक्रिय है। घटनाएं हर रोज हो रही हैं। इस गलियारे के जरिये आतंकवाद की भी मदद की जा सकती है। हालांकि 'शंघाई सहयोग संगठन' की बैठक के अंत में जारी एक साझा विज्ञप्ति में रूस, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान आदि देशों ने चीनी संपर्क पहल, 'वन बेल्ट वन रोड', के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। साफ है कि चीन पाक आर्थिक गलियारे के मुद्दे पर इस संगठन के अधिकतर देश भारत के निर्णय के विरोधी हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन में भारत की मौजूदगी के फायदे क्या हैं? संगठन के लगभग सभी देशों के साथ, पाकिस्तान को छोड़कर, भारत के व्यापारिक, सांस्कृतिक, राजनयिक रिश्ते हैं। शंघाई के कारण उनमें इजाफा नहीं हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत अकेली आवाज है, लेकिन उसकी गूंज 'आसमानी' है। भारत ने आतंकवाद को कई और वैश्विक मंचों पर उठाया है। उसे साझा घोषणा-पत्र में शामिल किया गया है। यदि वर्षों से भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है, तो उसकी बुनियादी वजह आतंकवाद ही है। भारत के प्रति पाकिस्तान का दुश्मनी और नफरत वाला व्यवहार किसी से छिपा नहीं है। जब शंघाई जैसे मंच पर आतंकवाद को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को अब भी कबूल नहीं करता, तो संबंधों में सुधार कैसे संभव है? यदि शंघाई के मूल रचनाकार चीन की भूमिका को देखा जाए, तो दक्षिण एशिया में तानाशाही और आतंकवाद के प्रति वह बिल्कुल भी गंभीर या ईमानदार नहीं है।

# 'मूरत' बदली पर क्या न्याय प्रणाली की सीरत भी बदलेगी?

**न्याय के निष्पक्ष होने के साथ यह भी आवश्यक है कि वह समय रहते मिले। अन्यथा उस न्याय का, चाहे वह कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। आपराधिक और दीवानी विवादों के जितने मुकदमे अदालतों में पहुंच रहे हैं, उस तुलना में उनकी सुनवाई करने और फैसला देने वालों जजों की संख्या बहुत कम है। भारतीय अदालतों में बुनियादी और अधोसरंचनात्मक सुविधाओं की कमी की तो अलग ही कहानी है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर सर्वोच्च अदालत में 'न्याय की देवी' की सूरत बदली है तो आगे न्याय प्रणाली की सीरत भी बदलेगी। लेकिन कैसे यह सवाल अभी बाकी है।**

आजादी के 75 वें साल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'न्याय की देवी'की आंखों से पट्टी हटाने का फैसला न्याय के प्रति नैतिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भले हो, लेकिन इससे देश में बेहद धीमी गति से काम कर रही न्याय व्यवस्था में सुधार और लोगों को त्वरित और स्वीकार्य कैसे मिलेगा, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। 'न्याय की देवी' के स्वरूप और तेवर का भारतीयकरण हो, यह अच्छा है, लेकिन न्याय प्रणाली अपने काम काज में भी 'देसी ढर्रे' पर ही चले, यह गंभीर चिंता का विषय है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रतीकात्मक बदलाव इस मायने में अच्छा है कि हम न्याय प्रणाली का भी स्वदेशीकरण करना चाह रहे हैं, भले ही हमे यह औपनिवेशिक व्यवस्था अंग्रेजों से विरासत में मिली हो। इस लिहाज सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी यूरोपीय शैली में 'न्याय की देवी' की वही प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसकी मूल अवधारणा रोमन सभ्यता की रही है। अर्थात एक रौबदार देवी के दाएं हाथ में न्याय की तराजू और बाएं हाथ में तलवार। देवी की आंखों पर पट्टी का अर्थ यह कि वह बिना पक्षपात के न्याय देगी। तराजू के मायने यह कि सभी पक्षों को समान रूप से सुना जाएगा और तलवार न्याय के पारदर्शी होने और कानून के पालन की गारंटी है। रोमन अवधारणा में यह देवी 'जस्टिशिया' है। हालांकि, इस न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी के कई अर्थ हैं, जिसमें से एक निष्पक्ष न्याय की जगह कानून के अंधा होने से भी है। कानून के मानवीय और और सामाजिक सरोकारों से परे होने से है।

यही कारण है कि ग्रीक और रोमन संस्कृति के वारिस आज यूरोप के कुछ देशों में 'न्याय की देवी' की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है। मसलन कनाडा में तो न्याय की देवी सिर से पैर तक केवल एक लबादा ओढ़े दिखती है। उसकी आंखे खुली हैं, लेकिन हाथों में न तो तराजू है और न ही तलवार। खुद रोम में न्याय की देवी के दाएं हाथ में तलवार की जगह पुस्तक दिखाई गई है। हो सकता है कि न्याय की नई भारतीय देवी के हाथों में तलवार की जगह संविधान देने का विचार इसी से आया हो।

वैसे भारतीय परंपरा में 'न्याय की देवी' जैसी कोई संकल्पना नहीं है। सनातन धर्म में शनि को ही न्याय का देवता कहा गया है। लेकिन शनि भय और अनिष्ट का प्रतीक ज्यादा हैं। इसका कारण शायद है कि भारतीय दर्शन में न्याय शास्त्र की विशद व्याख्या तो है, लेकिन ऐहिक जीवन में किए गए अपराधों की संहिताबद्ध विधि प्रणाली के जरिये सुनवाई कर दंड देने जैसी सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं है। हम जीवन को समग्र रूप देखते हैं और जीवनभर के पाप और पुण्य कर्मों का फल अगले जन्म में भोगने अथवा इन सबसे मुक्ति के बतौर मोक्ष पाने में विश्वास करते हैं।

यह फल धर्म और अधर्म के हिसाब से किए गए कार्यों के मुताबिक पुनर्जन्म में श्रेष्ठ अथवा निम्न योनि में जन्म के रूप में होता है। ऐसे में शायद भारतीयों को किसी 'न्याय की देवी' की अलग से कल्पना की जरूरत ही न पड़ी हो।

दूसरे, ज्यादातर विवाद पंचायत अथवा सामाजिक स्तर पर ही निपट जाते थे, इसलिए अलग से अदालत जैसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे, राजा ही सर्वोच्च अदालत था और उसका धर्माचरण ही न्याय की गारंटी था।

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में स्थापित नई प्रतिमा की स्थापना के पीछे परिकल्पना प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की है। वो चाहते थे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 'न्याय की देवी' की छवि भी भारतीय हो। यह बात मूर्तिकार विनोद गोस्वामी की कृति में भी दिखाई देती है। नई प्रतिमा में देवी का चेहरा भारतीय है। वह जस्टिशिया की तरह आक्रामक और रौबदार न होकर सौम्य है।

नई देवी रोमन स्त्रियों की तरह ट्यूनिक की बजाए साड़ी पहने हुए है।

उसकी आंखे स्पष्ट रूप से दुनिया देख रही हैं और दाएं हाथ में तलवार की जगह देश का राष्ट्रीय ग्रंथ 'संविधान' है। इसके पीछे यह संदेश देने की कोशिश भी है कि 'न्याय की देवी' की प्रतिबद्धता संविधान की भावना के अनुसार सभी को निष्पक्ष न्याय देने की है।

जज्बाती तौर पर 'न्याय की देवी' के भाव बदलने की यह कोशिश अच्छी है, लेकिन व्यवहार में इस देश में निष्पक्ष और त्वरित न्याय मिलने और कानून के प्रभावी अनुपालन की कहानी बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं है। इसका पहला कारण तो देशभर की अदालतों में न्यायाधीशों की कमी और न्याय प्रणाली का कछुए की चाल से काम करना है।

अगर अदालतो में पर्याप्त संख्या में जज ही नहीं होंगे तो फैसले जल्द कैसे होंगे?

भारत सरकार ने लोकसभा में 23 जुलाई 2023 को एक सवाल के जवाब में बताया था कि देशभर में निचली अदालतों में 5388 जजों के पद खाली पड़े हैं। देश की निचली अदालतों में जजो के स्वीकृत पद 25 हजार 246 हैं, लेकिन काम 19 हजार 858 ही कर रहे हैं। इन पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकारों को ही करनी होती हैं, लेकिन वहां भी हद दर्जे की लेतलाली है। राजनीतिक गुणा भाग हैं। जोड़ तोड़ है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर लगभग पूरी नियुक्तियां हो गई हैं, लेकिन हाई कोर्टों में 327 जजों के पद अभी भी खाली हैं।

एक तरफ जजों की कमी, दूसरी तरफ अदालतों में मुकदमों का बढ़ता अंबार। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देश की निचली अदालतों में कुल 5.1 करोड़ मामले में लंबित हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग मामलो की संख्या 82 हजार है जबकि हाई कोर्टों में 58.62 लाख मामले फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इनमें भी 42.64 लाख मामले तो दीवानी हैं। नई भारतीय न्याय संहिता में फौजदारी मामलों में तो फिर भी विवेचना की कोई समय सीमा तय की गई है, लेकिन दीवानी मामलों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। देश की अदालतों में 1 लाख 80 हजार मामले तो ऐसे हैं, जो 30 साल से चल रहे हैं।

इनका फैसला कब होगा, कोई नहीं जानता। ऐसे में पीढ़ियों तक मुकदमे चलते रहते हैं। नीति आयोग ने 2018 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अदालतों में इसी तरह धीमी गति से मामले निपटते रहे तो सभी लंबित मुकदमो के निपटारे में 324 साल लगेंगे। यह स्थिति तब है कि जब 6 साल पहले अदालतों में लंबित मामले आज की तुलना में कम थे।

न्याय के निष्पक्ष होने के साथ यह भी आवश्यक है कि वह समय रहते मिले। अन्यथा उस न्याय का, चाहे वह कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। आपराधिक और दीवानी विवादों के जितने मुकदमे अदालतों में पहुंच रहे हैं, उस तुलना में उनकी सुनवाई करने और फैसला देने वालों जजों की संख्या बहुत कम है। आज भारत में हर 10 लाख की आबादी पर औसतन 21 जज काम कर रहे हैं। जबकि यूरोप में यही औसत प्रति दस लाख 210 और अमेरिका में 150 जजों का है।

अगर हम अमेरिका के मानदंड को भी मानें तो भारत की 145 करोड़ की आबादी पर लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए कुल 2 लाख 17 हजार जज चाहिए जबकि हैं 20 हजार भी नहीं। जजों की नियुक्तियों का काम सरकार का है, लेकिन ज्यादातर सरकारें इस मामले में गंभीर नहीं दिखतीं।

परोक्ष रूप से यह रवैया जनता को न्याय के अधिकार के वंचित करने जैसा ही है। इसके अलावा भारतीय अदालतों में बुनियादी और अधोसरंचनात्मक सुविधाओं की कमी की तो अलग ही कहानी है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर सर्वोच्च अदालत में 'न्याय की देवी' की सूरत बदली है तो आगे न्याय प्रणाली की सीरत भी बदलेगी। लेकिन कैसे यह सवाल अभी बाकी है।

# बांग्लादेशी घुसपैठियों को जितना जल्दी हो बाहर करो...

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 24 मार्च, 1971 के बाद असम आने वाले सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उन्हें जितना जल्दी हो निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बांग्लादेशियों को नागरिकता दिए जाने को लेकर हुए असम समझौते के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6ए का विशेष प्रावधान वैध है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि एनआरसी डेटा को अपडेट करके बांग्लदेशी घुसपैठियों की पहचान और उनके निर्वासन की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर असम के पूर्व एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने आशंका जताई कि एनआरसी अपडेट में घुसपैठिये फर्जी दस्तावेज दिखाकर अपना नाम जुड़वा लेंगे और कोई नहीं निकाला जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह एनआरसी अपडेशन और घुसपैठियों के निष्कासन की प्रक्रिया की निगरानी करेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 25 मार्च, 1971 या उसके बाद असम आने वाले सभी बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन प्रवासियों का राज्य की संस्कृति और जनसांख्यिकी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकारों को इनकी पहचान, पता लगाने और निर्वासन में तेजी लानी चाहिए।

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने चार-एक के बहुमत से सुनाया। पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा। यह धारा दिसंबर 1985 में 15 अगस्त, 1985 को अस्तित्व में आए असम समझौते के अनुरूप पेश की गई थी। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार और असम के छात्र संघों के बीच हुआ था जो बांग्लादेशियों के बड़े पैमाने पर अवैध आवक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। धारा 6ए को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह नागरिकता प्रदान करने के लिए संविधान में निर्धारित तिथि से अलग है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। उसने यह भी साफ-साफ कहा कि 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच राज्य में आने वालों को कुछ शर्तों के अधीन 10 साल बाद ही नागरिकता दी जानी थी।

जस्टिस सूर्यकांत ने अपने और जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा के लिए 185 पृष्ठों का बहुमत का फैसला लिखा। इसमें धारा 6ए की वैधता के अलावा बांग्लादेशी प्रवासियों के अवैध प्रवाह के

कारण असम के निवासियों के सामने आने वाले सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संकट का भी जिक्र किया गया और इससे निपटने के उपाय बताए गए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में सिर्फ इतना बताया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए वैध है। हालांकि, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि धारा 6ए अब अप्रासंगिक हो गया है।

1947 में देश के विभाजन के बाद से बांग्लादेशियों का अवैध प्रवेश एक विवाद का विषय रहा है। भाजपा और असम गण परिषद (एजीपी) ने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरे और सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी को बदलने की साजिश के रूप में इसके खिलाफ अभियान चलाया है। वहीं, विरोधियों ने उन पर अवैध अप्रवासियों के मुस्लिम होने के कारण समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर असम में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत कमजोर हो गई और भाजपा वहां एक प्रमुख ताकत के रूप में उभर गई। दिलचस्प बात यह है कि आगामी झारखंड चुनावों में भी यह एक प्रमुख मुद्दा बन गया है।

जस्टिस सूर्यकांत ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों की अनियंत्रित घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए दो दशक पुराने एक फैसले का हवाला दिया। सर्बानंद सोनोवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि असम राज्य को बांग्लादेशी नागरिकों के बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन के कारण 'बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति' का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, जस्टिस सूर्यकांत , जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस मिश्रा ने कहा कि 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी धारा 6ए के तहत दिए गए सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। नतीजतन, उन्हें अवैध अप्रवासी घोषित किया जाता है। तदनुसार, धारा 6ए उन अप्रवासियों के संबंध में बेमानी हो गई है, जिन्होंने 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम में प्रवेश किया है।

बहुमत ने माना कि 25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान, पता लगाने और निर्वासन के लिए जारी किए गए निर्देशों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से, इसने पांच कानूनों का हवाला दिया। ये कानून हैं - अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950; विदेशी अधिनियम, 1946; विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964; पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; और पासपोर्ट अधिनियम, 1967। इन कानूनों को धारा 6ए के विधायी उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यानी 25 मार्च, 1971 के बाद किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को असम में प्रवेश नहीं करने देना। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सोनोवाल फैसले में दिए गए निर्देशों को 20 साल बाद भी ठीक से लागू नहीं किया गया है। विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष केवल 97,714 मामले लंबित थे जबकि लाखों अवैध बांग्लादेशी प्रवासी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब से ऐसे प्रवासियों का पता लगाने और निर्वासन की प्रगति की निगरानी करने का फैसला किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप्रवासन और नागरिकता कानूनों का कार्यान्वयन केवल अधिकारियों की इच्छा और विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

इस अदालत द्वारा निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। 94 पृष्ठों की अपनी राय में प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 6ए का विधायी उद्देश्य भारतीय मूल के प्रवासियों की मानवीय जरूरतों और भारतीय राज्यों की आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों पर प्रवासन के प्रभाव को संतुलित करना था। धारा 6ए में नियोजित दो मानदंड असम में प्रवासन और 24 मार्च, 1971 की कट-ऑफ डेट, उचित हैं।

# विमानों में बम रखने की झूठी सूचनाएँ और इसका समाधान

हवाई यात्रा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कभी-कभी सुरक्षा तंत्र को गुमराह करने के लिए झूठी सूचनाओं का सहारा लिया जाता है, जिनमें से सबसे गंभीर है बम की झूठी जानकारी देना। यह न केवल यात्री और विमान स्टाफ के लिए चिंता का कारण बनता है, बल्कि हवाई अड्डों की गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। बम की झूठी सूचना देने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसका तत्काल समाधान खोजना आवश्यक है। अक्सर हवाई अड्डों पर या उड़ान के दौरान ऐसी खबरें आती हैं कि किसी विमान में बम रखा गया है। यह सूचना जैसे ही संबंधित सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंचती है, तत्काल सुरक्षा प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। हवाई अड्डों पर आपातकालीन स्थिति घोषित होती है, विमान को रोका जाता है, यात्रियों और उनके सामान की विस्तृत जांच की जाती है, और कई बार विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई जाती है। इसके बावजूद, जब जांच के बाद पता चलता है कि बम की सूचना झूठी थी, तब तक हवाई अड्डे का परिचालन कई घंटों तक बाधित हो चुका होता है। इससे यात्रियों को मानसिक तनाव के साथ-साथ समय और धन का नुकसान होता है। बम की झूठी सूचनाएं कई कारणों से दी जाती हैं। कुछ लोग जानबूझकर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ मामलों में यह एक मजाक या व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से होता है। कई बार प्रतियोगी कंपनियां या आतंकवादी संगठन भी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं ताकि हवाई अड्डे की गतिविधियों को बाधित किया जा सके या विमान को किसी लक्ष्य से दूर किया जा सके। कई मामलों में, यह उन यात्रियों द्वारा किया जाता है जो किसी कारणवश उड़ान में देरी करना चाहते हैं या फिर अपनी किसी व्यक्तिगत परेशानी से परेशान होकर ऐसा कदम उठाते हैं। हाल के कुछ वर्षों में सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी घटनाओं की सूचना देना आसान हो गया है, जिससे यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है बम की झूठी सूचनाओं से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सुरक्षा पर पड़ता है। हर बार जब ऐसी सूचना मिलती है, तो सुरक्षा बलों को पूरी गंभीरता से काम करना पड़ता है। यह संसाधनों का भारी नुकसान है क्योंकि हर बार आपातकालीन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए भारी खर्च और समय लगता है।

1. मानव संसाधन का दुरुपयोग: सुरक्षाकर्मी, पुलिस, बम निरोधक दस्ते और अन्य आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सक्रिय किया जाता है, भले ही सूचना झूठी हो। इससे वास्तविक आपात स्थितियों में उनकी उपस्थिति और तत्परता प्रभावित हो सकती है।

2. वित्तीय हानि: ऐसी घटनाओं के कारण विमानों की देरी या उड़ान रद्द होने से हवाई अड्डों और एयरलाइंस को भारी वित्तीय नुकसान होता है। यात्री पुनर्निर्धारित उड़ानों का खर्च, हवाई अड्डे की गतिविधियों में बाधा, और सुरक्षा जांच की अतिरिक्त लागतों से बड़ी वित्तीय हानि होती है।

3. समय की बर्बादी: झूठी सूचना के कारण यात्रियों और स्टाफ का समय बर्बाद होता है। यात्रियों को उड़ान देरी का सामना करना पड़ता है और उन्हें लंबे समय तक जांच प्रक्रियाओं का हिस्सा बनना पड़ता है।

4. मानसिक तनाव: ऐसी झूठी सूचनाएं यात्रियों और हवाई अड्डे के स्टाफ के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। बम की सूचना किसी को भी मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, खासकर जब ऐसी स्थिति विमान के अंदर होती है।बम की झूठी सूचनाओं से निपटने के लिए सरकार और हवाई अड्डे की सुरक्षा एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि, इन घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए और भी कई समाधान अपनाने की आवश्यकता है।

1. कानूनी कड़े प्रावधान: बम की झूठी सूचनाएं देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान में कई देशों में ऐसे अपराधियों को भारी जुर्माना और कारावास की सजा दी जाती है। भारत में, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं जो उन्हें भारी जुर्माने और जेल की सजा का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे अपराधियों की संख्या में कमी नहीं आई है। इसलिए, कानूनी प्रक्रिया को और भी कड़ा और प्रभावी बनाना जरूरी है।

2. सुरक्षा तकनीक का उन्नयन: हवाई अड्डों पर अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना बम की झूठी सूचनाओं का जल्दी और प्रभावी ढंग से पता लगाने में मदद कर सकता है। उच्च स्तरीय स्कैनर, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली और बम डिटेक्शन तकनीकों को लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि बिना किसी देरी के सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. सोशल मीडिया निगरानी: सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली झूठी सूचनाओं को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की जा सकती है, जो तुरंत कार्रवाई कर सके।

4. यात्रियों की जागरूकता: यात्रियों को यह समझाना भी जरूरी है कि बम जैसी अफवाहें फैलाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए हवाई अड्डों पर जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, जिसमें यात्रियों को इस तरह की गतिविधियों से बचने की सलाह दी जा सके।

5. सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण: सुरक्षा बलों को इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनका प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए कि वे जल्दी और सही तरीके से स्थिति का आकलन कर सकें और समय रहते सही कदम उठा सकें।

विमानों में बम रखने की झूठी सूचनाएं एक गंभीर समस्या हैं, जिससे हवाई यात्रा की सुरक्षा और संचालन बाधित होते हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसके समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, फिर भी इस समस्या का जड़ से समाधान करने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई, उन्नत तकनीक और यात्रियों की जागरूकता की आवश्यकता है। जब तक झूठी सूचनाओं पर सख्त नियंत्रण नहीं लगाया जाता, तब तक हवाई अड्डों और विमानों की सुरक्षा पर खतरा मंडराता रहेगा।

**( राजीव खरे स्टेट ब्यूरो चीफ़ छत्तीसगढ़ )**

# दमोह में वाहन चेकिंग दौरान स्टॉपर तोड़ते हुए भागी स्विफ्ट कार, पुलिस ने पीछा कर पकड़ी

## कार में करीब 40 पेटी अवैध शराब बरामद

**धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ**

दमोह, जिले के पुलिस अधीक्षक सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के निर्देशन में जिलेभर में वाहन चेकिंग कार्रवाई लगातार जिले में जा रही है. हटा से स्थानांतरण होने के बाद देहात थाना की कमान संभालने वाले टीआई मनीष कुमार ने कार्यभार संभालते ही देहात थाना क्षेत्र में होने वाली गतिविधि पर नजर बनाते हुए कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, शुक्रवार शाम को टीआई सहित पुलिस देहात थाना के सामने वाहन चेकिंग कार्रवाई करते समय हटा की ओर से एक तेज रफ्तार शिफ्ट क्रमांक एमपी 20 सीए 8014 स्टॉपर को तोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन वह कार दमोह शहर के फुटेरा फाटक के समीप पहुंची, जहां फुटेरा फाटक का गेट लगा रहने के कारण वाहन चालक और मौजूद व्यक्ति स्विफ्ट कार को छोड़कर भाग निकले. वहीं देहात थाने में चल रही चेकिंग में नवागत टीआई मनीष कुमार ने तत्काल दो टीमें रवाना की, जो एक शहर की ओर तो दूसरी फुटेरा फाटक की ओर रवाना किया. जहां फुटेरा फाटक का गेट बंद होने के कारण वह शिफ्ट कार खड़ी मिल गई, जहां गेट बंद होने के कारण स्विफ्ट कार को तत्काल देहात थाना हंड्रेड डायल के माध्यम से लाया गया, जहां स्विफ्ट कार को खोलते ही देखा तो उसमें करीब 40 पेटी अवैध शराब बरामद की. पुलिस ने बताया कि 20 पेटी लाल और 20 पेटी प्लेन की कीमत लाखों में बताई गई है. जहां देहात थाना के सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह यह पूरी कार्रवाई कर आरोपितों की तलाश करने में जुटी हुई है. देहात थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर बनाकर यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. कार्रवाई में देहात थाने से सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह, प्रधान आरक्षक मुकेश दुबे, कामता, रवि कटारे, रामगोपाल, दिनेश, सतीश, आरक्षक देवेंद्र ठाकुर, अखिलेश छारी, रवींद्र अहिरवार, के अलावा और भी पुलिस बल के विशेष योगदान से यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. इस कार्यवाही के दौरान भारतीय शक्ति चेतना/भगवती मानव कल्याण संगठन की टीम भी मौके पर पहुंची थी

# एचडीएफसी बैंक के द्वारा नेमीनगर जैन मंदिर में रक्तदान शिविर आयोजित किया

**धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ**

दमोह। एच डी एफ सी बैंक के द्वारा नेमीनगर युवा मंडल के सहयोग से शरद पूर्णिमा के दिन समाधिस्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज जी के 79 वें जन्मोत्सव एवं नवाचार्य समय सागर जी महाराज के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जिसमें 45 लोगों ने जीव - दया की भावना को लेकर रक्तदान किया। शासकीय जिला चिकित्सालय अधीक्षक सिविल सर्जन डॉ राकेश राय के निर्देश पर ब्लड बैंक की चलित वाहन टीम द्वारा नेमीनगर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर ब्रम्हचारी अरुण भैया, ब्रह्मचारी मयंक भैया के मंगलाचरण कर किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी रतनचंद जैन घाट पिपरिया, इंद्रकुमार जैन ,डी के जैन ,डॉक्टर अमित जैन, ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट के अध्यक्ष महेंद्र जैन, समाजसेवी दीपक जैन, भूपेंद्र जैन के सहयोग एवं मार्गदर्शन से नेमीनागार युवा मंडल के सभी युवाओं, महिलाओं और नगर के अनेक समाजसेवियों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में एच डी एफ सी बैंक की ओर से समस्त रक्तदाताओं को मैनेजर बीरेंद्र जैसवाल और डिप्टी मैनेजर सौरभ जैन द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। युवा भूपेन्द्र जैन, राहुल जैन, रोहित जैन ने बताया कि रक्तदान महादान एक ऐसा कार्य जो जीवन बचाने और हमारे समाज में स्थायी बदलाव लाने की शक्ति को जागृत करने का काम करता हैं, इसी उद्देश्य को पूरा करने आचार्य श्री के जन्मोत्सव पर रक्तदान अभियान में सभी ने योगदान दिया। इस आयोजन पर रतन चंद जैन ने रक्तदान में आयोजक एच डी एफ सी बैंक,सिविल सर्जन डॉ राकेश राय और ब्लड बैंक की टीम के साथ नवयुवक मंडल के सभी सहयोगी युवाओं के उत्साह की सराहना की।

### रियल फोटो काफी के संचालक अपने साथियों के साथ राजनीतिक पहुंच के चलते चला रहे सुदखोरी कि दुकान

# सुदखोरों कि प्रताड़ना से आदिवासी महिला हुई परेशान लगाई पुलिस से न्याय कि गुहार

**लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ**

बालाघाट, जिले में इन दिनों सुदखोरी कि दुकान बहुत तेजी से चल रही है नियम को दरकिनार कर सुदखोर मनमानी तरीके से धौंस जमाकर कई गुना राशि वसूल रहे हैं,राशि नहीं देने पर सुदखोर मानसिंक रुप से परेशान भी कर रहे हैं जानकारी अनुसार कई लोगों के पास सुदखोरी का लाईसेंस भी नहीं है और दस परसेंट व पन्द्रह परसेंट तक राशि वसुली कर रहे हैं यह सब खेल पुलिस कि नाक के नीचे चल रहा है।

**ऐसा ही एक मामला बालाघाट से सामने आया है जिसमें एक आदिवासी महिला गायत्री मेरावी**

आयु 42 वर्ष निवासी बुढ़ी बालाघाट ने इन सुदखोरों से मानसिक रूप से परेशान होकर हैं। तथा इन सभी सुदखोरों कि शिकायत आदिवासी महिला ने 15 अक्टूबर 2024 को पुलिस थाना कोतवाली बालाघाट व पुलिस अधीक्षक बालाघाट से कि है तथा सभी सुदखोरों पर कार्यवाही कि मांग भी कि है, तथा इनके सुदखोरी कि लाईसेंस कि जांच कि भी मांग कि गई है।

**इन सभी सुदखोरों कि हुई शिकायत,कि जांच कि मांग**

वहीं शिकायतकर्ता आदिवासी महिला श्रीमती गायत्री मेरावी ने सभी सुदखोरों कि शिकायत कर जांच कि मांग पुलिस प्रशासन से कि है जिनमें लक्ष्मीचंद पिता शिवराम सहारे निवासी वार्ड नं 1 सिध्दार्थ नगर बुढ़ी बालाघाट,सावन पिता भाउलाल नगपुरे निवासी भटेरा बालाघाट, निर्मला टाकसांडे व जया टाकसांडे( दोनों निवासी वार्ड नं 1 बुढ़ी बालाघाट), सरोज नेवारे निवासी वार्ड नं 13 गंगा नगर बुढ़ी बालाघाट,निकेश कुथे निवासी बुढ़ी बालाघाट,नेहा पिता संतोष रहांगडाले (रियल फोटो काफी कर्मचारी) बालाघाट है।

**इन सभी विषयों को लेकर हुई शिकायत.... कार्यवाही कि आश**

वहीं शिकायत पत्र में उल्लेख है कि शिकायतकर्ता भटेरा बालाघाट में छोटी सी कपड़े कि दुकान चलाती है तथा शिकायतकर्ता का पुत्र भरवेली बालाघाट में डाक विभाग में कार्यरत है, शिकायतकर्ता श्रीमती गायत्री मेरावी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते 12जून 2023 को लक्ष्मीचंद सहारे (रियल फोटो काफी के संचालक) से ब्याजी तौर में 50 हजार रुपए प्रतिमाह 10 प्रतिशत कि दर से उसके हि फोटो काफी कि दुकान पर लिया गया एवज में पुत्र अजय मेरावी का युनियन बैंक आफ इंडिया शाखा बालाघाट के खाता क्रमांक 594402010017160 के दो कोरे चैक 242501व 242502 एवं सौ रुपए का कोरा स्टाम्प लक्ष्मीचंद सहारे को अमानत के रूप में उसी दिन दिया गया था।

पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा लगभग छः महीने में 9/12/2023 तक लक्ष्मीचंद सहारे को व उसके कहने पर उसकी कर्मचारी नेहा रहांगडाले को मय ब्याज से भी अधिक कि राशि 1लाख 80 हजार रुपए फोन पे व नगदी अदा कर चुके थे फिर भी लक्ष्मी चंद सहारे 20 हजार बाकी होना बताकर रुपए कि मांग करता रहा लेकिन शिकायकर्ता कि माली हालत गंभीर होने से पुनः लक्ष्मीचंद सहारे से 9/12/2023 को 50 हजार रुपए उधार लिया गया जिसे जोड़कर 70 हजार रुपए ब्याज लेना और शिकायतकर्ता से चालू कर दिया गया और कहा गया कि जब तक तुम 70 हजार रुपए मयब्याज सहित वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दोनों चेक व कोरा स्टाम्प वापस नहीं मिलेगा।

तत्पश्चात शिकायतकर्ता व उसके पति द्वारा नगदी एवं फोन पे से अभी तक उपरोक्त दोनों राशि मय ब्याज सहित 2 लाख 85 हजार रुपए अदा कर चुके हैं किन्तु लक्ष्मीचंद सहारे व उसके साथियों द्वारा शिकायतकर्ता व उसके परिजनों को और 3 लाख रुपए जबरन अवैध रूप से घर एवं दुकान में आकर गाली गलौच करते हुए व रास्ते में भी रोककर पैसे कि मांग करते हैं व मोबाइल फोन पर भी अवैध वसूली कि मांग करते हैं एवं दोनों चेक व स्टाम्प पेपर शिकायतकर्ता को वापस नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मीचंद सहारे द्वारा नेहा रहांगडाले पर दबाव डाला जा रहा है कि तेरे खाते मे गायत्री मेरावी व मोहन मेरावी द्वारा जमा करें रुपए के बारे में कोई जानकारी नहीं देना है।

साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा दो कोरे चैक व कोरा स्टाम्प पेपर गिरवी के रूप में रखकर सावन नगपुरे से 5/11/2022 को 50 हजार रुपए कि राशि 10 प्रतिशत प्रतिमाह कि दर से लिया गया था तथा सावन नगपुरे को भी मय ब्याज सुद के फोन पे व नगदी शिकायतकर्ता व उसके पति द्वारा एक माह में ही अदा कर दिया गया था किन्तु शेष राशि 5 हजार रुपए अदा नहीं कि गई थी इसी दौरान फिर से 2023 में 50 हजार रुपए सावनलाल नगपुरे उसी जमा अमानत या प्रतिभुति दो कोरा चेक व 1 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर जमा पर हि उसी ब्याज दर पर 10 प्रतिशत प्रतिमाह से अपने कपड़े कि दुकान पर ऋण लिया गया था और सावनलाल नगपुरे को भी आज दिनांक तक दोनों राशियों का मय ब्याज सहित 2लाख 70 हजार रुपए शिकायतकर्ता व उसके पति द्वारा फोन पे व नगदी के रूप में अदा किया जा चुका है किन्तु सावनलाल नगपुरे व उसके साथी दुकान व घर में आकर और 3 लाख रुपए कि मांग कर रहे हैं तथा दोनों चेक व स्टाम्प पेपर वापस नहीं कर रहे हैं साथ ही लक्ष्मी चंद सहारे व सावनलाल नगपुरे दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर केस बनाकर फंसाने कि धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि तेरे भी नाम का चेक कोर्ट में लगायेंगे,जबकि निकेश कुथे द्वारा शिकायतकर्ता के पुत्र जो डाक विभाग में कार्यरत हैं इसके विरुद्ध फर्जी कुटरचित चेक क्रमांक 242501 खाता क्रमांक 594402010017160 युनियन बैंक व फर्जी स्टाम्प पेपर के आधार पर 2 लाख 50 हजार रुपए का न्यायालय बालाघाट में परिवाद लगाया गया है वहीं निकेश कुथे को शिकायतकर्ता ने कोई चेक व स्टाम्प पेपर नहीं दिया है।

वहीं शिकायतकर्ता निर्मला टाकसांडे व सरोज नेवारे से दोनों का अपने नाम का एक एक कोरा चेक व स्टाम्प पेपर पर मार्च 2023 में सरोज नेवारे से 45 हजार रुपए लिया गया तथा मय ब्याज सहित 97हजार 750 रूपए आज दिनांक तक जमा किया गया, निर्मला टाकसांडे से 13 जुलाई 2023 को 20 हजार रुपए लिया गया था तथा मय ब्याज सहित 56 हजार 200 रुपया 23/2/2024 को दिया गया था।

फिर भी निर्मला ताककसांडे एवं उसकी पुत्री द्वारा शिकायतकर्ता को गाली गलौच कर एवं मोबाइल फोन पर धमकियां देते हुए जबरन अवैध रूप से 2 लाख रुपए कि मांग कर रहे हैं इसी प्रकार सरोज नेवारे भी शिकायतकर्ता को गाली गलौच देकर 45 हजार रुपए का 97 हजार 700 रुपए ब्याज सहित भुगतान करने के बाद भी गाली गलौच करते हुए जबरन अवैध रूप से और 3 लाख रुपए कि मांग कर रही है और सभी सुदखोरों कि राजनीतिक पहुंच है और झुठे केश में फंसाने कि धमकी दे रहे हैं।

वहीं अब सवाल यह है कि क्या जिले के अंदर ऐसा ही सुदखोरी का खेल चलता रहेगा,क्या आदिवासी महिला को पुलिस से न्याय मिलेगा।यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पुलिस कौन सी कार्यवाही सुदखोरों पर करती है या फिर जांच के नाम पर आदिवासी महिला को परेशान किया जाएगा।

# जिले के समस्त शासकीय छात्रावासो के वार्डन के साथ कलेक्टर ने ली बैठक

## की गई गहन समीक्षा, दिए गये अहम् दिशा-निर्देश

**धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ**

दमोह, जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावास, समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित समस्त छात्रावासो के वार्डन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिला कार्यालय सभा कक्ष में ली। उन्होंने एक-एक वार्डन से छात्रावास संचालन में आने वाली समस्याओं एवं छात्रावास में भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन मीनू, नामांकन, वार्डन एवं रसोइयों तथा स्वास्थ्य, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा कर समुचित दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर ने छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं यथा वेतन आवास व्यवस्था आदि के बारे में भी सहायक संचालक आदिम जाति रिया जैन को निर्देशित किया, सभी के वेतनमान आदि की समस्याएं समय सीमा में निराकृत की जाये। पेयजल, विद्युत, आधार अपडेशन, लोक सेवा केंद्र प्रबंधन, खाद्यान्न आदि की समस्याओं के लिए उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराकर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी वार्डन से कहा विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में कोई समझोता नहीं किया जायेगा तथा जो भी समस्याएं हैं, उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित करें तथा समय पर उनका निदान किया जाये। सभी छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता युक्त भोजन, स्वच्छ पेयजल एवं सुरक्षित आवास व्यवस्था मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक छात्रावास में मासिक स्वास्थ्य शिविर के आयोजन हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी को संपूर्ण जिले में मासिक कैलेंडर तैयार करने के लिये निर्देश दिए। बैठक में पीपीटी के माध्यम से समस्त छात्रावासों का एजेंडा अनुसार प्रेजेंटेशन दिया गया। आगामी बैठक के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि छात्रावासों से संबंधित जो अन्य विभाग हैं, जैसे फुड, जल निगम, विद्युत, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग आदि के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाए ताकि समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जा सके।

### त्रिस्तरीय पंचायत के अधिकार पुनः वापस पाने जनप्रतिनिधियो ने की मांग

# पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आह्वान पर सचिव को ज्ञापन सौंपा

**लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ**

लालबर्रा, तहसील मुख्यालय लालबर्रा में आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ग्राम पंचायत सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है उक्ताशय की जानकारी देते हुए लालबर्रा सरपंच अनीस खान,ग्राम पंचायत रमपुरी सरपंच कन्हैया राहंगडाले,जनपद पंचायत सदस्य लालबर्रा दीपक कावरे, ग्राम पंचायत निलजी सरपंच फिरोज खान,लालबर्रा जनपद पंचायत के पूर्व सदस्य शैलेश केकती द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि पूर्व में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे तब मध्यप्रदेश में पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत 1994 से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत से अधिकार दिये गए थे किंतु बाद में धीरे धीरे करके पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार सरकार द्वारा वापस ले लिये गए है। जिससे आम जनता व वास्तविक हितग्राही अपने अधिकारों से वंचित हो गए हैं, ग्राम वासियों के कार्य करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,जबकि पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के रहते सम्पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत,जनपद पंचायत व जिला पंचायत को रहा करते थे वे आज नही है पूर्व में ग्राम पंचायत ही बैठक में तय करती थी कि कौन पात्र हितग्राही है जिन्हें आवास मकान देना है, गरीबी रेखा कार्ड बनाना है,छोटे मोटे विवाद गाँव में ही ग्राम न्यायालय से खत्म करना है, पेंशन बनाना,कौन कौन से निर्माण कार्य करना है जैसे सभी निर्णय ग्राम पंचायत में तय होते थे किंतु सरकार द्वारा वर्तमान समय में ये अधिकार हटा लिए गए हैं अब तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि ना तो किसी हितग्राही का मकान स्वीकृत कर सकते ना ही गरीबी रेखा सूची में नाम जोड़ सकते और ना ही निर्माण कार्य स्वीकृत कर सकते अब सारे कार्य प्रकिर्या व आदेश के तहत होते निर्माण कार्य टाइड, अनटाइड क्या करना है,पंचायतों की राशि किस कार्य में खर्च करना है सब आदेश जारी के साथ होते हैं ग्राम पंचायत अब स्वतंत्र नही रही है,अधिकारियों कर्मचारियो का हस्तछेप बढ़ गया है। इस बात को लेकर ही आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने लालबर्रा में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा कार्यालय में पंचायत इंस्पेक्टर श्री खिलेंद्र सोनवंशी जी व सचिव ग्राम पंचायत श्री कृष्णा पंचेश्वर जी को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया।

लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी से प्रदेश स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने भेंट कर पंचायती राज के पुराने अधिकार वर्ष 1994 पुनः वापस दिलाये जाने की मांग की थी जिसपर पंचायत प्रतिनिधियों की मांग का समर्थन करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी खुलकर सामने आए और उन्होंने ही आज 18 अक्टूबर को सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों से अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में सचिवों को मांग पत्र का ज्ञापन देने अपील किये थे। लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को पुराने अधिकार वापस दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी का पूरा सहयोग मिल रहा है तथा आने वाले समय में पंच,सरपंच, जनपद सदस्य,जिला पंचायत सदस्यों को अधिकार पुनः वापस नही मीले तो दिग्विजय सिंह जी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बड़ा आंदोलन में भी हिस्सा लेंगे।

# दमोह में आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन के जांच दल द्वारा मिष्ठान निर्माताओं के निर्माण स्थलों का किया गया औचक निरीक्षण

**धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ**

दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल एवं खाद्य सुरक्षा जांच दल द्वारा दमोह शहर में मिष्ठान निर्माताओं के निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की कार्यवाही मागंज वार्ड, सत्कार लॉज के पीछे एवं जबलपुर रोड, आम चोपड़ा क्षेत्र में की गई। मागंज वार्ड, सत्कार लॉज के पीछे स्थित श्री राजस्थान मिष्ठान भंडार के मिष्ठान निर्माण स्थल के निरीक्षण में परिसर में गंदगी एवं साफ सफाई का अभाव देखा गया, मिठाइयों एवं कच्ची खाद्य सामग्री का उचित भंडारण नहीं पाया गया, अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, वेंटिलेशन की कमी, मिठाईयां बनाने में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री का उचित भंडारण नहीं पाया गया, कार्यरत कर्मचारियों को एप्रन, हेड कवर, हैंड ग्लव्स, मास्क का उपयोग करते हुए नहीं पाये जाने पर मौके पर संचालक को परिसर में समुचित साफ-सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

# बबरिया में शॉपिंग कांप्लेक्स निर्माण का हुआ भूमिपूजन...

### जिला पंचायत सभापति के मुख्य आतिथ्य,जनपद उपाध्यक्ष की अध्यक्षता व ग्राम सरपंच के नेतृत्व में भूमिपूजन

**लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ**

लालबर्रा, जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बबरिया में 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को शापिंग काम्प्लेक्स निर्माण कार्य का भुमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया,उक्त आयोजित कार्यक्रम जिला पंचायत सदस्य व सभापति झामसिंह नागेश्वर के मुख्य आतिथ्य,जनपद पंचायत उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल की अध्यक्षता व ग्राम पंचायत सरपंच मोहनलाल गौतम स्थाई पटेल तथा प्रभारी सचिव विजय ऐड़े के नेतृत्व आयोजित किया गया, जिसमें सभी पंचगण,मेट तथा ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों व प्रबुद्ध जन शामिल रहे। भूमिपूजन कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कांप्लेक्स निर्माण स्थल पर सूचना पटल के पास उपस्थित अतिथियों,व ग्रामीणों द्वारा बारी-बारी से भारत

माता का तिलक वंदन कर पुष्प अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, सरपंच, पंचगणों समेत सभी उपस्थित जनों द्वारा कुदाली चलाकर 7 कमरों के शापिंग काम्प्लेक्स का भूमिपूजन कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

उक्त भूमिपूजन पर सरपंच मोहन गौतम ने कहा कि यह निर्माण कार्य जिला पंचायत सभापति झामसिंह नागेश्वर के सहयोग से प्रधानमंत्री गौण खनिज मद से स्वीकृत कराया गया है,जिससे हमारे गांव के 7 परिवार के लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी। जिसके लिए समस्त बबरिया ग्राम पंचायत वासियों ने जिला पंचायत सदस्य व सभापति और सरकार का आभार व्यक्त किया है।

उक्त भूमिपूजन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपसरपंच गजानंद सहारे,पिपरिया (छिंदलई) सरपंच रूपचंद मानेश्वर,भोजराम पटले,लुकेश कुमार गौतम,खिलेश्वर भगत,ओमेंद्र पारधी,लक्ष्मण बानते,भुमेश्वरी गौतम,ज्योति गौतम,दुरगन राहंगडाले,निशा गौतम,देवगन रजक,लता हुमनेकर,रेखा ऐड़े,धनीराम रोकड़े,देवका झलपे,शिवप्रसाद ग्वाले, भुमेश्वरी,गोपाल तितरमारे, श्यामकला उईके,फूलसिंह उईके, मेट-उमराव शेन्द्रे,खुशयाल पटले, अनिल ब्रम्हे व जिनसीलाल शेन्द्रे सहित ग्राम के दर्जनों वरिष्ठ व प्रबुद्ध जन,जागरूक नागरिक, प्रभारी सचिव विजय ऐड़े, रोजगार सहायक प्रफुल्ल बिसेन मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

### होम डेकोरेशन शोरूम में भड़की आग

# लपटें देख कर दहशतजदा हुए लोग 3 दमकलों से पाया आग पर काबू

**उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ**

सतना, शहर के रीवा रोड स्थित एक होम डेकोरेशन आइटम के शोरूम में आग भड़कने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुआं देख कर लोग दहशतजदा हो गए। हालांकि देर रात तक चली कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक, सतना शहर की रीवा रोड पर भरहुत नगर मोड़ के पास स्थित होम डेकोरेशन और फर्निशिंग आइटम के शोरूम राजघराना में गुरुवार की रात लगभग 10 बजे आग भड़क उठी। शी रूम की छत से उठता धुआं और आग की ऊंची लपटें शहर में दूर तक दिखाई पड़ीं। शोरूम के बाहर भीड़ जमा हो गई नतीजतन भीड़ के कारण सड़क पर ट्रैफिक भी प्रभावित हो गया। पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई। आग लगने की सूचना मिलने पर कोलगवां थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। एक के बाद एक तीन दमकल वाहन भी पहुंचे। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। वे शोरूम की छत पर भी गए और खासी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पा लिया गया। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। हालांकि अभी नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है।

बताया जाता है कि इस शोरूम में पर्दे, बेडशीट, चादर, सोफा कवर के अलावा होम डेकोरेशन के सामान की बिक्री होती है। इसी तीन मंजिला बिल्डिंग में ऊपरी तल में गोदाम भी बना है। आग ने ऊपरी मंजिल और छत को अपनी जद में ले लिया था। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। कोलगां पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। होम डेकोरेशन व फर्निशिंग सामग्री के इस शो रूम में आग लगने के बाद यहां शो रूम के मालिक और पड़ोस की बिल्डिंग के स्वामी के बीच एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। शो रूम संचालक में पड़ोसी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आग उसकी बिल्डिंग में लगे पर्दे के कारण लगी। हालांकि पड़ोसी की बिल्डिंग के किसी भी हिस्से में आग नजर नहीं आ रही थी।

बताया जाता है कि इसके पूर्व भी राजघराना शो रूम में आग लगी थी। तब भी दोनों के बीच इसी बात पर विवाद हुआ था। राजघराने में आगजनि के मामले में नगर निगम ने शुरू की जांच, फायर अधिकारी सहित अतिक्रमण की टीम पहुंची। नगरनिगम सूत्रों के अनुसार राजघराना वाली बिल्डिंग का कोई नक्शा ही पास नहीं है। जब नक्शा ही पास नहीं है तो फायर का अन्य किसी बात की अनुमति का सवाल ही नहीं उठता। राजघराना बिल्डिंग के मालिक को अवैध निर्माण के संबंध में नगर निगम कई बार नोटिस भी दे चुका है लेकिन आज तक किसी नोटिस का कोई जवाब तक नहीं दिया गया। अब यहां सवाल यह उठता है कि नगरनिगम प्रशासन ऐसे बड़े लोगों के खिलाग कोई कार्यवाही।

# एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेन्द्र सिंह ने विविध आयोजनों में की शिरकत

### स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का दिया संदेश

**उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ**

सतना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके यूपी के प्रतापगढ़ में रहने वाले एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने सतना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होने कहा कि बॉलीवुड की नई फीचर फिल्म मामा की लाडो के प्रमोशन कार्यक्रम व शहीद सैनिक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला यह हमारा सौभाग्य है सभी को धन्यवाद प्रेषित क रते हुए उन्होने कहा कि सतना के वीरनई ग्राम में आयुर्वेदाचार्य डा.राजधर मालवीय के यहां मेरा इलाज चलता है तो वे बीच-बीच में सतना आते रहते हैं। इनके आयुर्वेद के इलाज से काफी आराम है। वे कहते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन से तुरंत राहत तो मिल सकती है परन्तु पूर्णतया राहत के लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। मेरी तो सरकार से भी अपील है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए लोगों को इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए। धर्मेन्द्र प्रताप

सिंह समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और वे स्टार प्रचारक भी भूमिका भी निभा रहे हैं। उन्होने आगे कहा कि इसके अलावा वे क्रांतिकारियों व शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए अभियान में भी शामिल है। वे हमेशा शहीदों के परिजनों के सम्मान व सुरक्षा के लिए साथ खड़े हैं। उनकी मंशा है कि शहीदों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा चौक-चौराहे होने चाहिए। उन्होने सभी से बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया।

# कोठी नवागत थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने थाना पहुंचकर कार्यभार संभाला

**उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ**

सतना, जिले के कोठी थाने का चार्ज मिलने के बाद नवागत थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने कार्यभार संभाल लिया उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय पर उचित न्याय दिलाने और गरीब, असहाय फरियादियों की पारदर्शिता पूर्वक फरियाद सुनकर उनको समय पर निष्पक्ष न्याय दिलाने का कार्य करूंगी । आगे कहा कि थाना क्षेत्र को अपराध मुक्त रखने व शांति व्यवस्था के सफल प्रयास करूंगी और किसी भी प्रकार का कानून के खिलाफ कार्य करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना उनकी प्रथम वरीयता

में शामिल हैं । उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हरे प्रतिबंधित पेड़ों को बिना परमिट यदि किसी व्यक्ति ने पेड़ों पर आरा चलाया तो उस पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ?। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पत्रकार देश का चतुर्थ स्तंभ है यदि किसी भी व्यक्ति ने पत्रकारों से अभद्रता की तों उसे बख्शा नहीं जाएगा कानून अपना काम करेगा।

# सद्भावना के सिपाही टीम द्वारा 11 बेटियों की फीस दी गई

**उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ**

सतना, सद्भावना के सिपाही टीम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा में मदद एक मिशन के अंतर्गत सतना मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा की मुख्य अतिथि में बेटियों की फीस दी गई कार्यक्रम संयोजक उमेश साहनी ने बताया कि गत वर्षो की भांति एस0एम0टी0ए0 के आर्थिक योगदान से 11 बेटियों की 11000/- रूपए फीस दी गई कार्यक्रम में प्राचार्य सुभाष चंद्र मिश्रा मोनिका अवस्थी सुजाता शर्मा जानवी साहू संजय अग्रवाल पवन मलिक रामचंद्र तिवारी अभिषेक जैन सुनील जैसवाल, पियूष शर्मा,सुरेंद्र गुप्ता नीलांबर झा गोल्डन,प्रवीण मित्तल अमित भावनानी, ब्रजकिशोर अग्रवाल, अर्चना मिश्रा मंजू द्विवेदी अनिता गौतम ददानी प्रसाद शर्मा आलोक त्रिपाठी बद्री प्रसाद

गौतम बृजेश विश्वकर्मा राधा पाठक ज्योत्सना तिवारी धर्मेश शुक्लाआदि स्टाफ उपस्थित रहा अंत में मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह देखकर सम्मानित किया गया!

# 22 वर्षीय गुमशुदा नवयुवती को कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा गोवा से दस्तयाब कर परिजनो के किया सुपुर्द

**सुशिल सोनी । सिटी चीफ**

अनूपपुर, दिनांक 05.09.2024 को थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 22 वर्षीय पुत्री दिनांक 05.09.2024 को तुलसी कॉलेज का जाने कहकर घर से निकली थी और लापता हो गई है, जो रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 117/2024 पंजीबद्ध किया जाकर तलाश पतासाजी की गई।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान के निर्देशन में थाना कोतवाली अनूपपुर से सहायक उपनिरीक्षक महिपाल नामदेव, आरक्षक गिरीश चौहान एवं महिला आरक्षक ज्योति धार्वे

के द्वारा जांच के दौरान रेल्वे स्टेशन अनूपपुर के सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं मोबाईल के काल डिटेल के आधार पर गुमशुदा नवयुवती को गोवा के पुलिस थाना वेर्णा अंतर्गत नवयुवती के मित्र के साथ दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। पूछताछ पर नवयुवती द्वारा बताया गया कि विगत तीन सालो से वह राहुल मेहरा पिता संतोष मेहरा उम्र करीब 23 साल निवासी ग्राम बटुरा थाना अमलाई जिला शहडोल से मित्रता एवं प्रेम संबंध में थी, जो गोवा में इण्डिगो कंपनी में प्रायवेट नौकरी करता है। अंतर्जातीय संबंध होने से परिवार जन को यह रिश्ता मंजूर नहीं था इसलिए नवयुवती द्वारा घर से भागकर गोवा पहुंचकर विवाह कर लिया गया है। पुलिस द्वारा नवयुवती को परिजनो को सौंपा गया है।

# कोतमा के स्कूली वाहन चालको की ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई आकस्मिक चेकिंग

### 06 स्कूलों के 19 वाहन चालकों को किया गया चेक

**सुशिल सोनी । सिटी चीफ**

अनूपपुर, शराब के नशे में वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक अनूपपुर की ओर से चलाया जा रहा है अभियान आज दिनांक 18/10/24 को ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोतमा शहर मे स्थित प्राइवेट स्कूल सेंट जोसेफ हाई स्कूल, ग्रीन लैंड स्कूल, भारत माता हायर सेकेंडरी स्कूल, सहित कुल 06 स्कूल के 19 स्कूली वाहन चालकों को ब्रइथ एनालाइजर से चेक किया ,जिसमें कोई भी चालाक शराब के नशे में नहीं पाया गया। वाहन चालकों को दी गई समझाइश आकस्मिक चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने के संबंध में समझाएं देते हुए बताया गया कि वाहन हमेशा निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, ओवरटेक करने

से बचे ,यदि आवश्यक की हो तो हमेशा दाहिने तरफ से ओवरटेक करें, ब्रेकिंग डिस्टेंस का ध्यान रखें, बच्चों को वाहन से उतारते समय सावधानी रखते हुए वाहन को रोड के बाएं साइड खड़ा करे उसके बाद उन्हें उतरने दे।क्षमता से अधिक बच्चे ना बिठाये, बच्चों के अभिभावक बहुत विश्वास के साथ आपकी गाड़ी में उन्हें स्कूल भेजते हैं ।कृपया सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए उन्हें घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाए।

**सावधानी से ही सुरक्षा है**

वाहन चालकों को बताया गया कि सावधानी और सतर्कता से सड़क दुर्घटना को घटित होने से रोका जा सकता है । चेकिंग में थाना प्रभारी यातायात, श्रीमती ज्योति दुबे, कोतमा थाने से सहायक उप निरीक्षक चंद्रहास बांदेकर प्रधान आर. रामधनी तिवारी, आर महेश गुर्जर एवं आरक्षक दिलीप सिंह उपस्थित रहे। शराब के नशे में वाहन चलाना सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है इससे बचे स्वयं की एवं अन्य व्यक्तियों के जीवन को संकट में ना डालें।

# सूदखोर परवेज अंसारी को बिजुरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

**सुशिल सोनी । सिटी चीफ**

अनूपपुर, इस प्रकार है कि दिनाक 17-10-24 को फरियादी लखन केवट पिता लक्ष्मण केवट उम्र 61 वर्ष निवासी जमुनिहा थाना बिजुरी का उपस्थित थाना आकर इस आशय का शिकायत प्रस्तुत किया कि वह कॉलरी का रिटायर कर्मचारी है] 02-03 वर्ष पूर्व अचानक पैसे की आवश्यकता पडने पर उसने परवेज अख्तर अंसारी निवासी मनेन्द्रगढ से ब्याज मे 25000/-रुपये उधार लिये थे जिसके बाद वह उक्त सूदखोर के जाल मे फॅस गया जिसने फरियादी का पासबुक,चेकबुक,आधार कार्ड,एटीएम,व मोबाइल धोखा देकर अपने कब्जे मे रख लिया फरियादी अपनी दैनिक आवश्यकताओ के लिये भी उक्त सूदखोर पर आश्रित हो गया,जून 2024 मे रिटायरमेंट के बाद उसके खाते में रिटायरमेंट के करीब 30 लाख रुपये आये थे जिसमें से 28,48,000/-रुपये आरोपी परवेज अख्तर अंसारी ने फरियादी से ब्याज और मूलधन के रुप में हडप लिया विरोध करने पर उसे चेक बाउंस और बलत्कार जैसे केश मे फसाने एवं पूरे परिवार को जान से खत्म कर देने की धमकी दी घटना विवरण पर से आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध अप क्र. 249/24 धारा 420,384,386,406 ताहि एवं 3,4 कर्जा एक्ट का थाना बिजुरी मे पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर श्री मोती उर्र रहमान जी ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन मे बिजुरी पुलिस द्वारा आरोपी परवेज अख्तर अंसारी पिता स्व. मोहम्मद हदीश अंसारी निवासी मोहार पारा मनेन्द्रगढ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायायिक अभिरक्षा मे पेश किया गया है आरोपी के कब्जे से फरियादी लखन केवट की पासबुक, चेकबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड, एटीएम, व मोबाइल और फरियादी के हस्ताक्षर किये हुए खाली चेक बरामद हुये है जिन्हे साक्ष्य हेतु जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया है। उक्त कार्यवाही मे बिजुरी पुलिस के निरीक्षक विकास सिंह] उनि सोने सिंह परस्ते] सउनि विपिन बिहारी राय] प्रआर. सतीश मिश्रा, आर. लक्ष्मण, आनंद, अनिल म.आर. संगम तोमर की महत्पूर्ण भूमिका रही।

# सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य

## ठेकेदार और नगर परिषद जनप्रतिनिधि की मिलीभगत होने की बात आ रही सामने

**यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ**

**बरगवां अमलाई।** नगर परिषद बरगवां अमलाई के हनुमान मंदिर परिसर से लेकर बापू चौक तक बनी पीडब्ल्यूडी की सड़क पर पेवर ब्लॉक ईट लगाकर की जा रही सौंदरीकरण सड़क निर्माण कार्य जो की वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 5 एवं 4 बापू चौक तक बनाया जाना टेंडर के मुताबिक सुनिश्चित किया गया है इस सड़क के निर्माण कार्य में दोनों तरफ बिजली के खंबे लगाकर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है जिसमें कुछ दिनों पूर्व निर्माण कार्य के दौरान की जा रही लापरवाही एवं अनमितता को लेकर नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस प्रकार हो रहे गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण कार्य पर उप यंत्री नगरीय प्रशासन के द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद भी शिकायत के लगभग 10 दिन बाद सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता की पुनरावृत्ति होने का कारण और इस प्रकार गुणवत्ता हीन सड़क निर्माण कार्य के होने पर नगर परिषद के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा वर्तमान में सड़क ठेकेदार के क्रियाकलापों और निर्माण कार्य को लेकर चुपी साधे रहने के पीछे क्या राज है यह एक चिंता का विषय और पहेली बना हुआ है क्योंकि सड़क निर्माण कार्य के दौरान जिन नियमों और प्रस्तावित कार्य प्रणालियों के तहत कार्य होना सुनिश्चित किया गया है वह बिल्कुल ही नहीं हो रहा है और ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से बिना किसी विरोध के अपने मन मुताबिक करोड़ों की राशि से स्वीकृत सड़क पर भ्रष्टाचार किए जाने और क्षेत्र के विकास के नाम पर ठगी करने की बू आ रही है यह जांच का विषय है। ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा सड़क निर्माण कार्य का ठेकेदार को दिए गए कार्य और उसके द्वारा निर्माण कार्य में किया जा रहे लीपा पोती के पीछे कौन दे रहा है संरक्षण इस प्रकार हो रहे गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण को नजरों के सामने देखकर भी छुपा रहे अपनी नज़रें कौन है यह सड़क का ठेकेदार।इस प्रकार गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण कार्य की जांच धरातल पर रहकर उसे निर्माण कार्य के निर्धारित मापदंडों के आधार पर नहीं हो रहे कार्य की जांच से से संबंधित विभाग एवं किसी जनप्रतिनिधि की साठ गांठ की पहेली कोई बूझ नहीं पा रहा है

# बछड़े को पार्षद पवन कुमार चीनी के सहयोग से अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान पहुंचाया गया

## गाय के बछड़े को अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के साथ पार्षद पवन कुमार चीनी ने बचाया

**यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ**

अनूपपुर, नगर परिषद बरगवां अमलाई के वार्ड क्रमांक 6 अंतर्गत मिडिल स्कूल के पास अज्ञात वाहन से ठोकर खाई हुई गाय के बछड़े के पैरों पर गंभीर चोट के कारण गाय चल नहीं पा रही थी, जिससे वह सड़क के किनारे पड़ी थी,जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान धनपुरी के संस्थापक राम दुबे को दी सूचना मिलते ही राम दुबे ने अपनी टीम को लेकर तत्काल बछड़े की सेवा में लग गए ,फिर बछड़े का उपचार किया गया फिर बाद में गौ सेवा संस्थान बछड़े को लेकर पहुंचाया गया,जिसमें विशेष रूप से सहयोग के प्रति नवगठित नगर परिषद बरगवां अमलाई के वार्ड क्रमांक 07 के पार्षद समाजसेवी पवन कुमार चीनी के द्वारा हमेशा की तरह इस बार भी उनके द्वारा बछड़े को अमलाई दुर्गा मंदिर के पास से गौ सेवा संस्थान धनपुरी पहुंचाने के लिए उन्होंने एक चार पहिया वाहन उपलब्ध कराया और उसी वाहन के माध्यम से बछड़े को सुरक्षित अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान पहुंचाया गया, साथ ही गाय के उपचार के लिए जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई है, अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के संस्थापक राम दुबे जो धनपुरी क्षेत्र मे आज 4 वर्षों से चोटील अवस्था के गाय माँ और भी अन्य जीवों के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं,राम दुबे ने कहा कि हम अपनी टीम के द्वारा जहां भी गौ माता को सेवा के प्रति निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं,जिसमें विशेष रूप से अमलाई,विवेक नगर, सोडा फैक्ट्री, बरगवां, देवहरा के आस-पास जो भी गौ माता की सेवा के प्रति जरूरत पड़ती तो हमारे समाजसेवी पार्षद वार्ड नंबर 07 पवन कुमार चीनी द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।साथ पवन चीनी द्वारा गणेश स्थापना में विशेष सहयोग पूरे क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया है, नवरात्र के समय उनके द्वारा ग्रैंड गरबा महोत्सव का आयोजन भी कराया गया जिसको लेकर पार्षद पवन चीनी मित्र मंडली की काफी तारीफें हो रही है ,और साथ ही साथ अनूपपुर तथा शहडोल जिले के अधिकतम दुर्गा पंडालो में पवन चीनी द्वारा सहयोग राशि प्रदान की गई है जिसके लिए कमेटी के सदस्यों ने पार्षद समाजसेवी पवन चीनी को भरपूर आशीर्वाद देते आ रहे है।

# कटनी के मोहित बालानी ने फोर्ब्स की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में पाया स्थान

## स्मार्टफोन रिव्यू में भारत में 85वीं रैंक

**सुनील यादव । सिटी चीफ**

कटनी, कटनी जिले के माधवनगर निवासी मोहित का नाम फोर्ब्स लिस्ट में आया है जिसने मध्यप्रदेश में मोहित ने चौथा स्थान हासिल किया है। फोर्ब्स ने इंडिया के टॉप-100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट जारी की, जिसमें देशभर के 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनके काम और प्रभाव के आधार पर जगह दी गई है। इस लिस्ट में जिले के मोहित ने मप्र का 4 स्थान पा इन्फ्लुएंसर में शामिल हुए है। जिन्होंने अलग पहचान बनाई है। मध्यप्रदेश के सबसे ऊंची रैंक 68वीं पर भोपाल के टेक इन्फ्लुएंसर नमन देशमुख हैं।

कटनी जिले के मोहित को पिछले साल भी बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन का अवॉर्ड भी मिल चुका है। कटनी के मोहित बालानी इस साल पूरे भारत देख में 85वीं रैंक पर हैं, जो स्मार्टफोन रिव्यू में खास पहचान रखते हैं। इंदौर के उज्जवल पहावा 89वीं रैंक पर हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। वही सिवनी जिले के गांव उगली के शिवम पटले 93वीं रैंक पर हैं। शिवम 2019 से टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें की कटनी क्रे मोहित बालानी प्रतिष्ठित व्यवसायी समाजसेवी बिहारी बालानी क्रे पुत्र है उनकी इस सफलता पर परिवार जनो मित्रो ने हर्ष व्यक्त किया है।

# मेड़ता रोड में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला

## सूने मकान से ज्वेलरी-कैश चुरा ले गए चोर

**एजाज़ अहमद उस्मानी । सिटी चीफ**

(राजस्थान) मेड़ता रोड, मेड़ता रोड कस्बे में लगातार हो रही चोरियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। कस्बे में आए दिन हो रही चोरियों से कस्बे वासी दहशत में है। मेड़ता रोड कस्बे में अब तक हुई चोरियों की घटना के दौरान अधिकतर आभूषण व नगद रुपए चोरी हुए हैं। शुक्रवार को कस्बे की कृष्णा नगर कॉलोनी में भी चोरी की घटना सामने आई है। मेड़ता रोड थाना क्षेत्र की कृष्णा नगर कॉलोनी में सूने मकान में बदमाशों ने सेंध लगाई है। अज्ञात बदमाश घर से नगदी सहित सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त पीड़ित परिवार अपने पैतृक गांव बिलाड़ा गया हुआ था। वही परिवार के मुखिया कालूराम सरगरा की रेलवे में नौकरी होने के कारण अपनी ड्यूटी पर गए हुआ था। परिवार का मुखिया रेलवे में टीटीई के पद पर कार्यरत है।वापस लौटने पर चोरी का पता लगा। पीड़ित ने चोरी की शिकायत थाने में दी है।

परिवार का मुखिया कालूराम सरगरा ने पुलिस को बताया कि बताया की वो नवरात्र पर्व पर माता की पूजा करने हेतु एवं अपने पैतृक गांव में कुछ काम चल रहा है उसके कारण परिवार के लोग गांव बिलाड़ा गए थे। घर पर कोई नहीं था। मकान के मेन गेट व अंदर दो कमरों का ताला लगाया था।

इस दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने राशि को घर की लाइट जलते देखा तथा शुक्रवार को सुबह परिवार जनों को फोन पर बताया कि तुम्हारा मकान की लाइट रात को जल रही थी जिस पर परिवार जनों ने युवक को मकान की जानकारी लेने के लिए कहा जिस पर युवक ने देखा तो पूरे मकान में सामान बिखरा हुआ था जिसकी सूचना उसने तुरंत पीड़ित परिवार को दी। सूचना पाकर परिवार के लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि घर में रखे सोने चांदी के जेवरात तथा एक लाख रुपए नगद रखी हुई राशि चोर चुरा कर ले गए हैं।

परिवार ने बताया कि चोर?100000 नकद, 5 तोला सोने की रखड़ी सैट, सोने के टॉप्स,8 तोला चांदी की पायजेब तथा सोने की अंगूठी सहित काफी सामान चुरा कर ले गए हैं। मेड़ता रोड पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से कावेराम हो रहा आर्थिक रूप से सशक्त

**गणेश वैष्णव । सिटी चीफ**

(छत्तीसगढ़) नारायणपुर, जिले के ग्राम भुरवाल निवासी कावेराम, पिता हिरूराम, जो खेती किसानी करके अपने एवं परिवार का पालन पोषण कर जीवन यापन कर रहे थे। जब उनको उद्यानिकी विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी मिली तब उन्होंने विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली और उद्यानिकी के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। धीरे-धीरे उनकी मेहनत और विभागीय योजनाओं से मिले लाभ का नतीजा सामने आने लगा है। कावेराम ने 2 हेक्टेयर भूमि में उन्नत तकनीक से करेला और टमाटर खेती शुरू की है, जिससे उनकी पहले की आय की तुलना में अधिक आय मिलने लगी है। पहले कावेराम सिर्फ़ धान की फसल लगाता था, जिसमें समय के साथ साथ उत्पादन में कमी होने लगी और लागत मे वृध्दि होने से आमदनी भी कम होती गई। उद्यानिकी विभाग द्वारा कावेराम को उद्यानिकी फसल करेला एवं टमाटर की खेती करने का सुझाव दिया गया और अब वह 35 से 40 क्विंटल करेला एवं टमाटर का उत्पादन कर रहा है, जिससे उसकी आमदनी में बढोत्तरी हो रही है। कावेराम को इस खेती से 1 लाख 14 हजार से अधिक की आमदनी हुई है और उसके घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। अब वह अपने गाँव में एक उदाहरण माने जाने लगा है जिसे देखकर आसपास कृषक भी उद्यानिकी की खेती करना शुरू कर रहे है। उद्यानिकी विभाग द्वारा उसे वर्ष 2023-24 में पैक हाउस निर्माण हेतु अनुदान राशि भी प्रदान की गई है।

## जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्र प्रभारियों को किया सचेत

# क्रय केंद्रों पर कृषकों को न हो किसी प्रकार की असुविधा

## सभी उपकरण रहे क्रियाशील

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ**

(उत्तर प्रदेश) सहारनपुर, जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत धान खरीद के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गयी। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप क्रय केंद्रों पर कृषकों को पेयजल, बैठने एवं पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कृषकों का भुगतान समय से कराना सुनिश्चित किया जाए। कृषकों के पंजीकरण में तेजी लाई जाए। किसानों के धान खरीद के समय ही उनके खाते को एनपीसीआई कराना सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम एवं मार्केटिंग इन्सपेक्टर संयुक्त रूप से धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर कल तक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं कि निर्धारित मानकों के अनुसार क्रय केन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध है अथवा नहीं। सभी उपकरणों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए एवं सभी उपकरण क्रियाशील रहे। जनपद के लिए 5000 मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि धान क्रय केन्द्रों पर क्रय 01 अक्टूबर से प्रारम्भ है जोकि 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। उन्होने कहा कि खाद्य विभाग के 11 एवं पीसीएफ के 10 सहित कुल 21 क्रय केन्द्र स्थापित किए गये है। धान का समर्थन मूल्य 2300 रूपये प्रति कुन्तल एवं ग्रेड ए का 2320 रूपये प्रति कुन्तल घोषित किया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी आर0पी0पटेल सहित अन्य धान खरीद से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

# चोरों ने बनाया शराब के ठेके को निशाना

### शटर तोड़कर करीब 3.52 लाख रुपये कीमत की शराब की 112 पेटी चोरी की

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ** (उत्तर प्रदेश) सहारनपुर, सहारनपुर जनपद के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के उनाली गांव में चोरों ने एक शराब के ठेके को निशाना बनाते हुए ठेके का शटर तोड़कर उसमें से करीब 3.52 लाख रुपये कीमत की शराब की 112 पेटी चोरी कर ली। हैरानी की बात यह है कि बराबर दुकान में सो रहे सेल्समैन को चोरी होने की भनक तक नहीं लगी। पता लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां से एक तमंचा बरामद हुआ है। सेल्समैन रोजाना की तरह रात 10 बजे ठेका बंद कर घर चले गए थे। सुबह आकर जब ठेका खोला तो देखा कि पीछे की तरफ से शटर टूटा हुआ है। सेल्समैन ने शटर टूटे होने की जानकारी मालिक प्रवेश को दी। पता लगते ही प्रवेश मौके पर पहुंच गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब शराब पेटी की गिनती की गई तो उसमें करीब 112 पेटियां कम मिलीं, साथ ही गल्ले को तोड़कर 3500 रुपये भी चोरी हुए मिले। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एक देशी तमंचा भी मिला है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि शराब ठेके में चोरी होने की जानकारी है। पीड़ित की तरफ से तहरीर आ गई है। पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

# एक युद्ध नशे के विरूद्ध निकाली गयी रैली

### दीपावली पर एक दीया नशे को समाप्त करने के लिए जरूर जलायें : अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण आयोग

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ** (उत्तर प्रदेश) सहारनपुर, अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0 डॉ0 देवेन्द्र शर्मा, द्वारा एक युद्ध नशे के विरूद्ध रैली का शुभारम्भ हरी झण्डी दिखाकर किया गया। रैली में लगभग 2000 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसमें मुख्य रूप से कक्षा 10 व 12वीं की छात्र-छात्राओं, एन0सी0सी0 कैडेट्स, एन0एस0एस0 की छात्र-छात्रायें, आँगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहुयें तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रतिभाग किया गया। रैली सतयुग आश्रम मॉडल इण्टर कॉलेज, घंटाघर से के0सी0सी0पी0 इण्टर कॉलेज गिल कॉलानी तक निकाली गयी। रैली में माननीय अध्यक्ष द्वारा लोगों से आवाहन किया गया कि इस वर्ष दीपावली के अवसर पर अपने-अपने घरों में एक दीया नशे को समाप्त करने के जरूर जलायें। उन्होंने छात्र-छात्राओं से समाज को नशा मुक्त बनाने का आग्रह किया और कहा कि आओ सब मिलकर समाज को नशा मुक्त बनायें। उन्होंने यह भी कहा पूरे समाज को नशा मुक्त बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, जिला विद्यालय निरीक्षक हर्षदेव स्वामी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल, जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक कुमार पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी नन्दलाल, विशेष किशोर पुलिस इकाई से संदीप अधाना आदि उपस्थित रहे।

# विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल सदस्यों के द्वारा दो संदिग्ध गाड़ी चोरो को पकड़ कर किया गया कोतवाली पुलिस के सुपुर्द

**यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ**

अनुपपुर, अनुपपुर में 18/10/2024 की रात्रि 10बजे के आस पास विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल के सक्रिय कार्यकर्ता एव सजग नागरिक ललित कुमार दुबे रामभुवन मिश्रा एवं हिमांशु गुप्ता द्वारा दो संदिग्ध गाड़ी चोरी को पकड़ कर कोतवाली पुलिस अनुपपुर के सुपुर्द किया

घटना विवरण। 18तारीख रात्रि संदिग्ध हालत में खड़ी बिना नंबर एक टू वीलर मोटर साइकल श्री त्रिभुवन मिश्रा जी के घर एव दुकान के पास थी जिसकी जानकारी पुलिस को होने पर पुलिस द्वारा गाड़ी जप्त कर थाने ले जाया गया उस गाड़ी के मालिक को भी गाड़ी पहचान हेतु पुलिस द्वारा साथ लाया गया था गाड़ी त्रिभुवन मिश्रा जी के घर के पास खड़ी होने के कारण पुलिस द्वारा त्रिभुवन मिश्रा जी से गाड़ी के बारे में पूछताछ की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर पर न रहने के दौरान कोई गाड़ी खड़ी कर गया होगा , पुलिस द्वारा गाड़ी ले जाने के कुछ समय बाद लगभग एक घंटे बाद दो लड़के जो संदिग्ध है उनके द्वारा। त्रिभुवन मिश्रा जी की दुकान में लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया की हम यह गाड़ी खड़ी करके गए थे गाड़ी लेने आए है , जिस पर मिश्रा जी को शक हुआ तो उन्होंने बहाना बना कर उन्हें दुकान पर बैठने कहा और अपने मित्र ललित दुबे एवं हिमांशु गुप्ता को कॉल कर जानकारी दी जिस पर ये दोनो वहां पहुंच गए एवं कोतवाली पुलिस प्रमुख श्री अरविंद जैन जी को फोन कर जानकारी दी इसी बीच आरक्षक राशिद खान वहां से निकल रहे थे तब ये देख रुक कर जानकारी ली एवं हमराह स्टाफ को बुलवा कर संदिग्ध दोनों रवि राठौर एवं दीपक राठौर को कोतवाली पहुंचाया जहां इन दोनों संदिग्ध रवि राठौर एव दीपक राठौर निवासी पटोरा टोला अनुपपुर से पुलिस पूछताज कर रही है ।।

एवं 4 दिन पूर्व चोरी गई गाड़ी इनके पास कैसे आई इसकी जानकारी निकल रही है।

## बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त

# हमास ने कबूला- इजराइली हमले में याह्या सिनवार की मौत

**यरूशलम:** हमास ने शुक्रवार को पुष्टि की कि उसका नेता याह्या सिनवार गाजा में इजराइली बलों के हमले में मारा गया है। साथ ही चरमपंथी संगठन ने अपना यह रुख दोहराया कि एक साल पहले इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक गाजा में संघर्ष विराम नहीं होता और इजराइली सैनिकों की वापसी नहीं होती। इससे एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक देश की सेना लड़ती रहेगी और हमास को कमजोर करने के लिए गाजा में तैनात रहेगी।

दोनों पक्षों का यह रुख इस बात का संकेत देता है कि दोनों ही संघर्ष को समाप्त करने के करीब नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और दुनिया के अन्य नेताओं ने कहा है कि सिनवार की मौत एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जिसका इस्तेमाल रुकी हुई संघर्ष विराम वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए होना चाहिए। कतर में रहने वाले सिनवार के सिपहसालार खलील अल-हैया ने कहा, ''गाजा में हमलों के समाप्त होने और गाजा से सैनिकों की वापसी से पहले वो कैदी आपके पास नहीं लौटेंगे।%%

हमास ने बयान में सिनवार को नायक बताया है और कहा है कि ''वह एक वीर शहीद के रूप में उभरे, आगे बढ़े और पीछे नहीं हटे, अपने हथियार लहराए, अग्रिम मोर्चे पर कब्जा करने वाली सेना से भिड़ गये और उसका सामना किया।%%

इजराइली सैनिकों के साथ बुधवार को हुई मुठभेड़ में सिनवार की मौत गाजा युद्ध के समीकरण को

बदल सकती है। दूसरी ओर इजराइल दक्षिणी लेबनान में जमीनी सैनिकों के साथ हिजबुल्ला के खिलाफ अपने हमले को जारी रखे हुए है और देश के अन्य क्षेत्रों में हवाई हमले कर रहा है। इजराइल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला ने लगभग हर दिन इजराइल में रॉकेट दागे हैं।

हमास और हिजबुल्ला दोनों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जिसने सिनवार को शहीद बताया जो इजराइल को चुनौती देने के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकता है। इजराइल ने गाजा में हमास को राजनीतिक रूप से तबाह करने का संकल्प लिया है और सिनवार को मार गिराना सेना की शीर्ष प्राथमिकता में था। घटनास्थल पर इजराइली सैनिकों द्वारा ली गई तस्वीरों में एक व्यक्ति का शव दिखाई दे रहा है जो सिनवार का लग रहा है जो मलबे में आधा दबा हुआ था तथा उसके सिर पर गहरा घाव था।

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार रात सिनवार की मौत की घोषणा करते हुए अपने भाषण में कहा, ''हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है।%% लेकिन इजराइल के सहयोगी देशों की सरकारों से लेकर गाजा के थके हुए निवासियों तक, कई लोगों ने उम्मीद जताई कि सिनवार की मौत युद्ध के अंत का मार्ग प्रशस्त करेगी। इजराइल में गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने मांग की है कि इजराइल सरकार सिनवार की मौत को अपने प्रियजनों को वापस लाने के संबंध में बातचीत फिर शुरू करने के मार्ग के रूप में इस्तेमाल करे।

गाजा में अभी करीब 100 बंधक हैं और इजराइल के अनुसार करीब 30 बंधक मारे जा चुके हैं।

उधर लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्ला ने शुक्रवार को इजराइली सैनिकों के खिलाफ लड़ाई का एक नया चरण शुरू करने की कसम खाई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने सिनवार को श्रद्धांजलि देते हुए एक बयान जारी कर कहा कि वह इराकी नेता सद्दाम हुसैन के उलट युद्धभूमि में मारा गया है, छिपते हुए नहीं। हुसैन को फांसी दी गई थी।

## शहबाज शरीफ ने जो बाइडेन को लिखा पत्र

# जेल में कैद पाकिस्तानी महिला की रिहाई की मांग

**इंटरनेशनल डेस्क.** पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को पत्र लिखकर उस पाकिस्तानी महिला की रिहाई की मांग की है, जो आतंकवाद के आरोप में अमेरिका में 86 साल की जेल की सजा काट रही है। यह जानकारी इस्लामाबाद की एक अदालत में शुक्रवार को सरकारी वकील ने दी। शहबाज शरीफ के पत्र की एक प्रति अदालत में पेश की गई, जहां अमेरिका में प्रशिक्षित तंत्रिका तंत्र विज्ञानी आफिया सिद्दिकी की बहन की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। आफिया को 2010 में अमेरिकी नागरिकों की हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

आफिया का नाम तब चर्चा में आया, जब उसने अमेरिका छोड़ दिया और 11 सितंबर 2011 को हुए आतंकवादी हमलों के कथित साजिशकर्ता खालिद शेख मोहम्मद से शादी कर ली। 2008 में अफगानिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ झड़प के दौरान वह घायल हो गई थी और कहा जाता है कि उसने अमेरिकी अधिकारियों पर गोली चलाई थी।

शरीफ के 13 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आफिया ने अब तक 16 साल जेल में बिताए हैं और मामले को दया की नजर से देखने की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसके स्वास्थ्य और उपचार को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जिससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। शरीफ ने बाइडन से अनुरोध किया कि आफिया की बहन की क्षमादान याचिका स्वीकार की जाए और मानवीय आधार पर उसकी रिहाई का आदेश दिया जाए।

# अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमतें, भारत में आज नजर आएगा असर

**इंटरनेशनल डेस्क:** अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की अनिश्चिताओं के बीच अमेरिका में सोने की कीमतें अब तक के अपने सबसे रिकॉर्ड स्तर पहुंच गईं हैं। इस वर्ष सोने की कीमत में 30% से अधिक का इजाफा देखा गया है। पिछले महीने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में .50 प्रतिशत की कटौती के साथ-साथ आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं के कारण सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। भारत में इसका असर कल बाजार खुलने के साथ ही नजर आएगा। खबर लिखे जाने तक अमेरिका में स्पॉट गोल्ड 0.6% बढ़कर 2690.14 डॉलर प्रति औंस हो गया। अमेरिकी गोल्ड वायदा 0.5% बढ़कर 2,705.80 डॉलर पर पहुंच गया। बता दें कि अगले महीने यानी नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। रिपब्लिकन उम्मीदवार कमला हैरिस और डेमोक्रेट उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़े मुकाबला लग रहा है। इस बीच भारत के सर्राफा बाजार में सोना 450 रुपये की तेजी के साथ एक नये रिकॉर्ड स्तर 79,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बुधवार को पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 78,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 450 रुपये चढ़कर 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि, चांदी 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।

कारोबारियों ने कहा कि त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की लिवाली बढ़ने और वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी से सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के वायदा कारोबार में दिसंबर डिलिवरी वाला सोना का अनुबंध 77,019 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।

# फ्रांस: पानी में डूबी प्रवासियों से भरी नाव, बाल-बाल बचे 65 यात्री

**इंटरनेशनल डेस्क.** फ्रांस के तट पर प्रवासियों से खचाखच भरी एक नाव डूब गई, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 65 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है और एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नाव पर यात्रियों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण अधिक वजन होने से यह हादसा हुआ।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल था। यात्री चीख-पुकार करते हुए अपनी जान बचाने के लिए पानी में इधर-उधर भागे। नाव पर मौजूद लोगों ने एक-दूसरे की मदद की, जब स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत बचाव दल को मौके पर भेजा। बचाव दल ने 65 यात्रियों को सुरक्षित दूसरी नाव पर शिफ्ट कर दिया, जिससे उनकी जान बच गई।

**दम घुटने से हुई बच्चे की मौत**

स्थानीय नौसेना के अनुसार, इस हादसे में एक बच्चा बेहोश मिला। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चे की मौत दम घुटने और सदमे के कारण हुई है। उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।

**जांच एजेंसी का समुद्र में पहरा**

फ्रांसीसी समुद्री अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार रात फ्रांस के तट के पास चैनल में ब्रिटेन जा रही प्रवासियों से भरी एक नाव डूब गई। इस घटना का कारण नाव का अधिक वजन बताया जा रहा है। इस वर्ष फ्रांस में समुद्र में डूबने से करीब 52 प्रवासियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले 3 सितंबर को 12 बच्चों की भी इसी तरह से डूबने से मौत हुई थी। कई प्रवासी गैर-कानूनी तरीके से फ्रांस में घुसने का प्रयास करते हैं। स्थानीय जांच एजेंसियां समुद्र में गश्त लगा रही हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

## हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ा अमेरिका

# अब इन दो कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

**वाशिंगटन:** अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ड्रोन के इंजन और पुर्जे बनाने वाली दो चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि इन कंपनियों ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम ड्रोन बनाने में रूस की सीधे मदद की जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया गया। पाबंदी लगाने की घोषणा से पहले नाम न बताने की शर्त पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने पहले चीन पर इस बात के लिए आरोप लगाया था कि वह यूक्रेन के खिलाफ क्रेमलिन के युद्ध को जारी रखने के लिए रूस के सैन्य-औद्योगिक आधार को भौतिक सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवीनतम प्रतिबंधों का उद्देश्य बीजिंग और मॉस्को के बीच 'प्रत्यक्ष गतिविधि को निशाना बनाना है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि ड्रोन रूसी रक्षा कंपनियों के सहयोग से चीन में डिजाइन और निर्मित किए गए जिनका उपयोग यूक्रेन में युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए किया गया। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बीजिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि वह यूक्रेन या रूस को हथियार उपलब्ध नहीं कराता है तथा उसने रूस के साथ अपने व्यापार

को सामान्य तथा पारदर्शी बताया है। अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन इंजन बनाने वाली जियामेन लिम्बाच एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी और रूसी कंपनी के साथ काम करने वाली रेडलेपस वेक्टर इंडस्ट्री पर अमेरिकी प्रतिबंध लगा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों चीनी कंपनियां वर्ष की शुरुआत से ही रूसियों के साथ मिलकर लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन विकसित कर रही थीं। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने टीएसके वेक्टर के लाभकारी स्वामी रूसी नागरिक आर्टेम मिखाइलोविच यामशिकोव और रूसी संस्था टीडी वेक्टर के खिलाफ प्रतिबंधों की भी घोषणा की है।

# भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच कनाडा में ट्रूडो के चार मंत्रियों ने छोड़ा मैदान

**इंटरनेशनल डेस्क:** भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच ट्रूडो सरकार के चार मंत्रियों ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। इन चारों मंत्रियों की घोषणा के बाद जस्टिन ट्रूडो जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे और नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जिन मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। उनमें फिलोमिना टासी, मेरी क्लाउड, डेन वेंडल और करला क्वाल्ट्रो शामिल हैं। दरअसल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कनाडा में अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गई है। एंगस रीड इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक पिछले साल सितंबर में, कनाडा की 39 प्रतिशत जनता उन्हें नकार रही थी। जबकि, अब ये आंकड़ा बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया है। पिछले साल तक कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता 51 प्रतिशत थी जो अब गिरकर 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी लिबरल में ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और पार्टी के ही कई नेता उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के पक्ष में हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को लग रहा है कि वह लिबरल पार्टी के अकेले नेता हैं, जो अगले चुनाव में पार्टी को बहुमत के आंकड़े तक लेकर जा सकते हैं। इस बीच सीबीसी के पोल ट्रैकर ने भी ट्रूडो की लिबरल पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी कंजरवेटिव के मुकाबले 20 प्रतिशत प्वाइंट से पिछड़ती हुई नजर आ रही है।

दरअसल, अपनी घरेलू नाकामी से ध्यान हटाने के लिए ही जस्टिन ट्रूडो राष्ट्रवाद और संप्रभुता का मुद्दा उठा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कनाडा में विदेशी दखल के मुद्दे को हवा दी है। भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के अलावा ट्रूडो ने कनाडा में विपक्ष के नेता पोलीवर पियरे की पार्टी के सांसदों पर भी विदेशी दखल के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि, पियरे ने पलटवार करते हुए ट्रूडो से उन सांसदों की सूची मांगी है। जिन पर विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569